R N No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश
वर्ष 21 अंक 09 05 मई 2021

जगत विज़न

कोराना का कहर

सरकारों की नाकामी से देश संकट में

जन-जन के साथ कोरोना से जूझते शिवराज

जनयोद्धा बनें कमलनाथ

सिंधिया खेमे के स्वास्थ्य मंत्री ने मध्यप्रदेश को बनाया मौत की मंडी

Scanned with CamScanner

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	विन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राव
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 21 अंक 09 05 मई 2021

सरकारों की नाकामी से देश संकट में

जन-जन के साथ कोरोना से जूझते शिवराज

जनयोद्धा बनें कमलनाथ

(पृष्ठ क्र.-6)

कोरोना संक्रमण को रोकने में असफल साबित हुई भूपेश सरकार

कोरोना संक्रमण में राज्य को नंबर-1 बनाना चाहते हैं भूपेश बघेल

(पृष्ठ क्र.-46)

- बीजेपी हारी नहीं, ममता बैनर्जी जीता 52
- निजी अस्पतालों में सांसो की कालाबाजारी 56
- दिल्ली में कोरोना से हाहाकार 60
- India's Covid mismanagement : Thousand die 62

Scanned with CamScanner

हाल ही में मैंने जगत विज़न मासिक पत्रिका का अप्रेल 2021 का अंक पढ़ा। यह छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की दुर्दशा पर केन्द्रित है। छत्तीसगढ़ ने कैसे पत्रकारों को पंगु बनाकर परेशान किया जा रहा है। वह सारी व्यथा स्टोरी में प्रकाशित है। प्रदेश की भूपेश सरकार ने राज्य के पत्रकारों को कब-कब और कैसे अत्याचार किया। सबकुछ बताया गया है। पत्रिका की कवर स्टोरी पढ़कर मुझे काफी व्यथा महसूस हो रही है। किसे और किस तरह सत्ता लोगों को परेशान करती है।

राजेश महाजन, छत्तीसगढ़

सत्ता और शासन में बहुत ताकत होती है। वह चाहे तो किसी को भी बेवजह परेशान कर सकती है। जिसकी मिसाल पेश की है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने। प्रदेश की सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को पंगु बना कर रख दिया है। यहां की सत्त पत्रकारों को अपने हिसाब से चला रही है। और जो पत्रकार सरकार के खिलाफ लिखते है, बोलते है उन्हें काफी परेशान किया जाता है। पत्रिका के वाकई सच्चाई को प्रकाशित किया है।

जोवद खान, रायपुर

जगत विज़न के अप्रैल 2021 के अंक में देश के सबसे बड़े किसान आंदोलन में प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पत्रिका ने वाजिब सवाल किया है कि आखिर कब जाकर थमेगा किसान आंदोलन? यह सवाल देश के सभी लोग पूछना चाहते है। क्योंकि आंदोलन कई रूप देखे है और समय भी काफी हो गया है। लेकिन अभी तक कोई हल निकलने का अंदेशा नही लग रहा है। केन्द्र सरकार को भी चाहिए कि वह अब कोई न कोई हल ढूढ़ने का प्रयास करें।

अंकुर तिवारी, दिल्ली

यह वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है। सारे देश में हाहाकार मचा है लोग दहशत में है। कोरोना के चलते लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है, अपनों ने साथ छोड़ दिया है। रोजगार छिन गये है, व्यापार ठप पड़ गया है। ईलाज के लिए मारामारी मच रही है। लोगो को चिंता सता रही है कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। सरकार हाथ पर हाथ रखे रखी है। हालात बेकाबू हो गये है। भय और मातम का माहौल गांवों तक पहुंच गया है। मेरा निवेदन है कि पत्रिका में कोरोना को लेकर भी स्टोरी प्रकाशित होनी चाहिए।

नरेश कुमार, ग्वालियर

पत्रिका में पाठकों की राय का स्वागत है। संदेश भेजकर सुझाव देने के लिये धन्यवाद। आप अपने सुझाव ई-मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ई-मेल द्वारा भेजे गये सबसे अच्छे पत्र को पुरस्कृत किया जायेगा।

संपादक
जगत विजन
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)
e-mail : jagat.vision@gmail.com, Visit at : www.jagatvision.com

Scanned with CamScanner

तालिबान से वापस जायेगा अमेरिका

अफगानिस्तान में कट्टरपंथी तालिबान से करीब 20 साल तक लड़ने के बाद इस साल अमेरिका का आखिरी सैनिक भी सितंबर में वहां से वापस लौट जायेगा। अमेरिका और तालिबान के बीच पिछले दिनों हुए एक समझौते के बाद ऐसा हो रहा है। समझौते के मुताबिक, अब अफगानिस्तान में शांति कायम करने में तालिबान भी सहयोगी होगा और वहां की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बनेगा। इस साल 29 फरवरी को कतर की राजधानी दोहा में हुए समझौते के मुताबिक, तालिबान अपने यहां अलकायदा जैसे संगठनों को पनाह नहीं देगा, जो अमेरिका के लिए परेशानी खड़ा करें। तालिबान अपने वादे पर कितना कायम रहेगा, यह तो भविष्य की बात है। इतना जरूर है कि अफगानिस्तान में मौजूद विदेशी सैनिकों पर हमले बंद हो गए हैं, पर इसके विपरीत स्थानीय लोगों की मुसाबतें फिर से बढ़ने लगी हैं। फिर तालिबान ने भी समझौते की भाषा छोड़ यह एलान कर दिया है कि इस युद्ध में उसने अमेरिका को हरा दिया है। ऐसे में यह विश्लेषण स्वाभाविक है कि 2001 के बाद से अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से स्थानीय लोगों को क्या मिला। यह कैसे हुआ कि ताकतवर देश अमेरिका लगभग हार की स्थिति में अफगानिस्तान से वापस हो रहा है। इस हलचल का पड़ोसी भारत और पाकिस्तान पर क्या असर होगा? हाल के एक अध्ययन के मुताबिक, पाकिस्तान में तालिबान के सुरक्षित अड्डे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई जैसे संगठनों के जरिए तालिबान को मजबूती मिली। वर्ष 2018 में अमेरिकी सहयोग से एक अफगानिस्तानी अध्ययन के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबानियों को सैन्य और खुफिया सहयोग प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी सैनिक, अफगानी सुरक्षा बल के जवान और वहां के नागरिक मारे गये। यहां ज्ञातव्य है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान सहयोगी बना हुआ था। जैक रीड कहते हैं कि यह विरोधाभासी स्थिति रही। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी आर्थिक मदद के बदले हमें अपने हवाई क्षेत्र और अन्य सुविधाओं का उपयोग तो करने दिया, पर तालिबानियों की भी मदद करता रहा। अपने यहां पनाह पाए तालिबानी नेताओं को वह वार्ता के लिए राजी करता रहा किंतु वादे के विपरीत ऐसे पनाहगारों को संरक्षण भी देता रहा। जैक रीड को इस बात की तकलीफ है कि अमेरिका पाकिस्तान में तालिबानी अड्डों को नष्ट नहीं कर पाया। अब अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद अपने अच्छे रिश्तों के कारण पाकिस्तान तालिबानियों से दोस्ती की स्थिति में रहेगा। यह अफगानिस्तान के अंदर दूसरे पक्ष (चुनी हुई सरकार) से उसकी दूरी को और अधिक बढ़ाएगी। जहां तक भारत की बात है, हमने अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार से ही रिश्ते रखे हैं। यही नहीं, वहां की संसद, कई बांध और सड़क निर्माण सहित बड़ी परियोजनाओं में भारत सहयोगी है। उसका विपुल धन, संसाधन और इंजीनियर लगे हुए हैं। शांति समझौते के मुताबिक तालिबान भी वहां की व्यवस्था में भागीदार हुआ तो भारत को दिक्कतें हो सकती हैं। फिर वह नए सिरे से तालिबान से रिश्ते दबनाना चाहे तो पाकिस्तान को असहजता होगी। बहरहाल, एक आंकड़े के मुताबिक, पिछले करीब 20 साल में तालिबान के विरुद्ध जारी युद्ध में अमेरिका के करीब दो हजार 300 सैनिक मारे गए। संघर्ष के दौरान 20 हजार से भी अधिक अमेरिकी सैनिक चोटिल हुए हैं। इसके मुकाबले अफगानी नागरिकों और सेना को कहीं अधिक नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 2009 में ही स्वीकार किया था कि सिर्फ पांच साल में 45 हजार अफगानी सैनिकों ने इस संघर्ष में जान गंवाई है। ब्राउन यूनिवर्सिटी ने अपने एक शोध में 2001 के बाद 64 हजार से भी अधिक अफगानियों के मारे जाने की जानकारी दी थी। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन के मुताबिक तो यह संख्या एक लाख 11 हजार से भी अधिक है। जहां तक खर्च की बात है, अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस दौरान 143 अरब, 27 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। अमेरिका ने ३ ६ अरब डॉलर अफगानिस्तान सरकार और विकास योजनाओं पर लगाए तो अफगानिस्तान नेशनल आर्मी और वहां के पुलिस बल के प्रशिक्षण पर भी भारी रकम खर्च की है। यह सब कुछ अफगानिस्तान के बहाने दुनिया से कट्टरपंथ के असर को कम करने के लिए हुआ। अब जबकि अफगानिस्तान की व्यवस्था में तालिबान भागीदार होगा, बहुत कुछ उसके अगले रुख पर निर्भर करेगा।

विजया पाठक

Scanned with CamScanner

सरकारों की नाकामी से देश संकट में

जन-जन के साथ कोरोना से जूझते शिवराज

जनयोद्धा बनें कमलनाथ

सिंधिया खेमे के स्वास्थ्य मंत्री ने मध्यप्रदेश को बनाया मौत की मंडी

Scanned with CamScanner

भारत सहित मध्यप्रदेश में कोरोना हाहाकार मचा रहा है। चारों ओर त्राहि-त्राहि मची है। शहर, नगर क्या अब तो हालात गांवों के भी बदतर हो गए हैं। अप्रैल के शुरूआत से आए आकड़े अब लाखों में पहुँच गए हैं और मरने वाले लोग भी हजारों में जा पहुँचे हैं। हालात इतने बदतर हो गए कि सरकार भी काबू में नही कर पा रही है। अस्पतालों में जगह नही, दवाऐं नहीं। लोगों को आराम नहीं। वर्तमान समय इतिहास का सबसे खराब समय चल रहा है। लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस सबके बीच प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मसीहा के रूप में उभरकर लोगों की मदद कर रहे हैं। यह दोनों ही इस संकट की घड़ी में धरातल पर कार्य कर रहे हैं। बाकी नेता तो तमाशा देख रहे हैं। हालात को देखते हुए लग रहा हैं कि अभी भी प्रदेश की जनता को परेशानियों से जूझना पड़ेगा क्योंकि अभी हालात काबू में नही हैं। हालात को देखते हुए विपक्ष के नेता कमलनाथ दिनरात कर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे समय में राजनीति न करते हुए समाजसेवा को अपना जरिया बनाया। यह काबिले तारीफ है। उनकी इस पहल की सराहना होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार के मुखिया शिवराज अकेले ही हालात को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। खैर जो कुछ भी स्थिति बनी है वह चिंतनीय है लोग दहशत में हैं। अपने आप ही टूट रहे हैं। आगे क्या होगा, समझ नही आ रहा है। कोरोना महामारी ने हम सब को तोड़कर रख दिया हैं। कईयों ने अपनों को खो दिया है। कई लोग जिंदगी से जूझ रहे है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हालात जल्द से सुधर जाए और लोग राहत की सांस लें।

विजया पाठक

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आए दिन इस संक्रमण की चपेट में आकर आए दिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। हर तरफ कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं बेड तो कहीं रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कमी को लेकर लोग परेशान हैं। अस्पतालों में हालात इतने बेकाबू है कि लोगों को सही ढंग से इलाज तक नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की फिलहाल राहत दिखाई नजर नहीं पड़ती। आए दिन पूरे प्रदेश में हजारों लोगों की मौत हो रही है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और अधिकारी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या महज आठ से दस ही बताते हैं। बल्कि राजधानी के अलग-अलग विश्रामघाटों पर जलने वाली लाशों को देखने के बाद हकीकत कुछ और ही नजर आती है। पूरे प्रदेश में अब तक 5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं। वहीं, अब तक 70 हजार से ज्यादा मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में पांच लाख से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस हैं। जबकि आए दिन प्रदेश में मिलने वाले मरीजों की अब संख्या 13 हजार से ऊपर हो गई है। सिर्फ राजधानी की बात

Scanned with CamScanner

कोरोना को कन्ट्रोल करने में शिवराज ने किए रात-दिन एक

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोनाकाल के कठिन समय में अपने आप को समर्पित कर दिया। चौबीसो घंटों उन्होंने कोरोना को लेकर काम किया। मीटिंग के जरिए प्रदेश के कौने-कौने से अवगत होते रहे और जहां भी जिस चीज की जरूरत पड़ी उसकी पूर्ति करवाई। साथ ही केन्द्रीय सरकार से भी जरूरत के सामान की उपलब्धि करवाई। यह अलग बात है कि सीएम के चौकन्ना रहने के बावजूद प्रदेश में हालात बेकाबू रहे लेकिन शिवराज सिंह ने अपने स्तर पर कुछ भी लापरवाही नही बरती। अफसोस रहा कि सीएम का साथ उनके मंत्रि-मंडल के सदस्यों ने नही दिया। अकेले शिवराज ही कोरोना से जंग करते रहे। बाकी मंत्री तो बंगलों में घुसकर बैठ गए। जिसका ही नतीजा रहा कि कोरोना से निपटने के वह परिणाम नही आ आए जिनकी उम्मीद जताई जा रही थी। हालात बदतर होते गए फिर भी पूरी सरकार सहयेग करने में कतराती रही। यहां तक कि बातें भी होने लगी अकेले शिवराज कैसे स्थिति को संभाल पाएंगे।

करें तो बीते दो सप्ताह से भी अधिक समय से भोपाल में हर दिन 1900 से ज्यादा केस आ रहे हैं। वहीं, प्रतिदिन 700 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। जबकि मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 3 लाख 59 हजार 755 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 82 हजार 268 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब स्वास्थ्य विभाग इलाज के पर्याप्त संसाधन जुटा लेने के दावें कर रहा है तो फिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु क्यों हो रही है? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। प्रदेश सहित भोपाल में इतनी बड़ी संख्या

Scanned with CamScanner

पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना

मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस महामारी से उपजे हालात के बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया राज्य में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, जहां दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, एंबुलेंस और बेड की सुविधा हो। सीएम ये कहकर झूठ बोल रहे हैं कि प्रदेश में सबकुछ पर्याप्त है। पिछले तीन महीने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए सतर्क कर रही थी। कमलनाथ ने आगे कहा कि भाजपा लाशों पर राजनीति कर रही है। उन्हें लगता है कि वो सच्चाई छिपाकर कोरोना महामारी को रोक लेंगे मगर ऐसा होगा नहीं। मालूम हो कि देश में कोविड-19 संक्रमण से भयावह स्थिति बनी हुई है। कमलनाथ ने कोविड-19 के कुप्रबंधन के लिए भाजपा नीत राज्य सरकार पर निशाना साधा और इसे प्रशासन की तरफ से की गई आपराधिक लापरवाही बताया। कमलनाथ ने यह भी आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में मौत के आंकड़ों को दबाने और छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। कमलनाथ ने कहा मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरी लहर के लिए कोई प्रबंध नहीं किया। हमारे स्कूल-कॉलेज बंद हो गये, परीक्षा निरस्त हो गये, लेकिन राजनीति चलती रही, रैली चलती रही। उन्होंने कहा, आज ये हालात हैं कि प्रदेश में जिस संख्या में लोगों की (कोरोना से) मृत्यु हो रही है, उसको दबाने का और छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। शमशान घाट एवं कब्रिस्तान में कितनी लाशें आ रही है और कितना छाप रहे हैं। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा, शिवराज सिंह जी मुझे पूरे प्रदेश में एक अस्पताल का नाम बता दें जहां इंजेक्शन, दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर एवं बिस्तर पर्याप्त मात्रा में हैं। और शिवराज के लिए सब कुछ पर्याप्त हो गया। उन्होंने आगे कहा, लापरवाही जो है ये एक आपराधिक लापरवाही है। मैं तो इसे आपराधिक लापरवाही कहता हूं। कमलनाथ ने कहा है कि वह मध्यप्रदेश को इस तरह मरते नहीं देख सकते हैं।

में मरने वाले मरीजों का एक बड़ा कारण है उन मरीजों का अकेलापन। उन्हें इलाज के दौरान उनके परिजनों से न मिलने दिया जाना। सरकार को तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश के कोविड केयर सेंटर में यह व्यवस्था लागू करना चाहिए कि एक कोविड पेशेंट के साथ उनका एक परिवार का व्यक्ति देखभाल के लिए रखा जाए। उस व्यक्ति को पीपीई किट पहनाकर एक से डेढ़ घंटे के लिए मरीज के पास भेजा जाना चाहिए ताकि कम से कम परिवार का व्यक्ति मरीज को एक संबल और साहस देने का काम करें। ज्यादातर मरीज तो सिर्फ इसलिए अपनी हिम्मत छोड़ रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में दूसरे मरीजों की हालत देखकर वो हैरान है। एक के बाद एक उसके

Scanned with CamScanner

लोगों के मददगार बने कमलनाथ

अपने गृह जिले छिंदवाड़ा की जनता के हर सुख दुख में शामिल होकर उनका ध्यान रखना और उनसे कमल नाथ का आत्मीय लगाव किसी से छिपा नहीं है। महासंकट की इस घटी में मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने जनता को जीवनदायनी और बड़ी राहत देने वाली सौगात दी है। आम लोगों के इलाज के लिए कमल नाथ व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं करते चले आ रहे हैं। छिंदवाड़ा, नागपुर, भोपाल जैसे शहरों में इलाज कराने की बात हो या दवाइयों की व्यवस्था करना। कमल नाथ कभी पीछे नहीं हटे। अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के नक्शे कदम पर ही चलते हुए छिंदवाड़ा के युवा सांसद नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा जिले को एक विशेष कोरोना अस्पताल की सौगात दी है, जो अपने आप में बहुत ही अहम है, क्योंकि सांसद ने इस कोरोना अस्पताल के लिए किसी शासकीय राशि का उपयोग नहीं किया है। लगातार क्षेत्रीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों से जानकारी ले रहे थे और कुछ दिन पहले ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि स्थिति बिगड़ने वाली है, पिछले माह हुई दिशा समिति की बैठक में भी उन्होंने प्रशासन को इस बारे में आगाह किया था, इसी अंदेशे के कारण उन्होंने समय के पहले ही अमरावती की संस्था सरस्वती हरवानी चेरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख डॉ. अरुण हरवानी से सम्पर्क किया। नागपुर और मुंबई की तरह एक विशेष कोरोना अस्पताल छिंदवाड़ा की जनता के लिए तैयार करने का निर्णय लिया। इस संस्था द्वारा पहले से 105 बिस्तर का विशेष कोरोना अस्पताल अमरावती में संचालित है। जिले में शासकीय अस्पताल में ही कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था, इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी इलाज आसानी से

ही आसपास होती मौतें उसे जीने का साहस छुड़वा देती है। इतना ही नहीं एक ओर उदाहरण है जनसंपर्क के एक अन्य अधिकारी राजेश मलिक की पत्नी की मौत। प्रदेश के एक वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी एम्स जैसे अस्पताल में बेड के लिए

Scanned with CamScanner

नहीं मिल पा रहा था। क्षेत्रीय जनता को इलाज में तकलीफ आ रही थी, और विशेष स्थितियों में भोपाल और नागपुर की ओर देखना पड़ रहा था, लेकिन अब रानी कोठी में नया स्पेशल कोविड हॉस्पिटल बन जाने से इन सभी समस्याओं से निजात मिलेगी। इसके अलावा भोपाल, ग्वाललियर, बालाघाट, इंदौर जैसे महानगरों में भी उन्होंने आक्सीजन, इंजेक्शन जैसी दवाएं उपलब्ध करवाई हैं। लोगों को जैसी जरूरत वैसी मदद की है और आज भी कर रहे हैं।

यह हो रही व्यवस्थाएं

रानी कोठी में जो अस्थाई कोविड हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें आईसीयू बेड, बाइपेप यूनिट और वेंटीलेटर की व्यवस्था रहेगी। गम्भीर रोगियों का इलाज किया जाएगा। सामान्य रोगियों के लिए पृथक वार्ड की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में 65 बिस्तर की कैपेसिटी के साथ अस्पताल तैयार किया जा रहा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाकर 100 बेड तक किया जा सकता है। अस्थाई कोविड अस्पताल में विशेषज्ञ, चिकित्सक तथा वे सारे संसाधन उपलब्ध होंगे जो कोरोना का इलाज करने में आवश्यक है। अस्पताल में न्यूनतम शुल्क पर समस्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलाज की व्यवस्था की जा रही है। सांसद नकुल नाथ, क्षेत्रीय विधायक तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अस्पताल की व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

इंजेक्शन और ऑक्सीजन की नहीं कमी

सांसद नकुल नाथ ने पूर्व में ही लगभग 318 रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने खर्चे पर जनता को उपलब्ध करा चुके हैं। आने वाले समय में कोरोना के ईलाज में

दरबदर भटकती रही और अंततः जब तक उसे बेड मिला तब तक वो सांसे छोड़ चुकी थीं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब प्रदेश के इतने प्रभावशाली लोगों के साथ इस तरह की घटना हो रही है तो अन्य जिलों में आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा यह सोच

Scanned with CamScanner

लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन और सभी दवाइयों की व्यापक स्तर पर व्यवस्था बनाने में सांसद अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी की खबरें पूरे प्रदेश से लगातार आने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ और सांसद नकुल नाथ ने अपने व्यक्तिगत सम्बंधों के आधार पर ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले प्लांट के मालिक से सीधी बात की और कलेक्टर छिंदवाड़ा से भी बात करवाई। छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन सप्लाई में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा की वैक्सीन लगाने के बावजूद लोगों को कोरोना हो रहा है। प्रदेश की स्थिति गंभीर है। रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हैं। वैक्सीन खत्म होने की कगार पर है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों से कोरोना को लेकर बातचीत की। कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ द्वारा अब तक छिंदवाड़ा के कोरोना मरीज़ों के लिए 133 टन ऑक्सीजन, कमलनाथ के पिता महेंद्रनाथ ट्रस्ट के ज़रिय 200 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1000 के लगभग रेमडीसीवीर इंजेक्शन, 50,000 के ऊपर फेबिफलु दावा भेजी गई है।

उल्लेखनीय है कि देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या पिछले साल सात अगस्त को 20 लाख को पार कर गई थी। वहीं कोविड-19 मरीजों की संख्या 23 अगस्त को 30 लाख, पांच सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी। कमलनाथ ने यह भी आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में मौत के आंकड़ों को दबाने और छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।

पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज को लिखी चिट्ठी, कोरोना कंट्रोल के लिए दिये ये 12 सुझाव

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने मध्यप्रदेश में कोरोना कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ सुझाव दिये हैं। उन्होंने एक पत्र सीएम को लिखा है जिसमें 12 बिंदुओं पर सुझाव हैं। कमलनाथ ने इन सभी सुझावों पर प्रभावी अमल करने का आग्रह भी किया है।

■ कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को गहनता और तीव्रता से लागू करने की आवश्यकता है।

■ उम्र के बंधन को समाप्त कर प्रदेश के प्रत्येक आमजन को कोरोना वैक्सीन नि:शुल्क लगाई जाये।

■ पहली लहर और वर्तमान में अधिक संक्रमित क्षेत्रों की पहचान कर वहां वैक्सिनेशन का काम प्राथमिकता से किया जाए।

■ कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता और सुरक्षित स्टोरेज करने से इस अभियान में तेज़ी आएगी।

■ कोरोना वैक्सीन की जिलों में उपलब्ध न होने के कारण काम प्रभावित हो रहा है। इसलिए प्रदेश के सभी केंद्रों पर वैक्सीन समय पर सप्लाई की जाए।

■ स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य की सहायता लेकर घर-घर जाकर लोगों को वैक्सिनेशन सेंटर तक आने के लिए प्रेरित किया जाए।

■ कोरोना की जांच के लिए रैपिड टेस्ट की संख्या और गति बढ़ाई जाए। घर-घर जाकर टेस्ट किये जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो सके। व्यापक और नि:शुल्क टेस्टिंग से कोरोना काबू में करने में मदद मिलेगी। टेस्ट की रिपोर्ट कम से कम समय जैसे 8 घंटे में जारी की जाए।

■ ट्रेसिंग सर्वे के काम में भी गति लाई जाए।

■ कोरोना की निजी अस्पतालों में जांच की दर न्यूनतम तय की जाए। इसके लिए लगातार निगरानी और सख्त व्यवस्था हो।

■ कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज की पुख्ता व्यवस्था की जाए।

■ प्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए आईसीयू, एचडीयू बेड और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता लगभग समाप्त हो गई है। इस विषय पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, अन्यथा स्थिति भयावह होगी।

■ अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्ध हो, इसके लिए तत्काल आवश्यक निर्णय लिये जाएं। प्रदेश के ऐसे ऑक्सीजन प्लांट जो किसी कारण से बंद हैं, उन्हें फौरन फिर से चालू किया जाए।

कर ही रूह कांप उठती है। एक सवाल और जेहन में आता है कि आखिर सरकार अस्पतालों से मरने वाले मरीजों की मौत का कारण क्यों नहीं पूछती। इतना ही नहीं चिरायु हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों द्वारा एक मरीज से ऑक्सीजन मास्क निकालकर दूसरे मरीज

Scanned with CamScanner

कमलनाथ मसीहा हैं-प्रवीण पाठक, विधायक ग्वालियर

कमलनाथ तो मसीहा हैं। वह एक ऐसे एकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी तरफ से मुझसे पुछा कि ग्वालियर में कोई परेशानी तो नही है। हमने उनसे कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन नही मिल रहे हैं। और उन्होंने विधायक ग्वालियर ईस्ट सिकरवार दोंनों को इजेक्शन भिजवाने की व्यवस्था की। तब से अभी तक इजेक्शन की कमी नही हुई। हम रात भर कलेक्टर, एसपी, विधायक ऑक्सीजन की परेशानी को लेकर पूरे शहर में घूमते रहे क्योंकि आक्सीजन खत्म हो गया था। तीन दिन तक भय का वातावरण बन गया था। कब किस की मृत्यु हो जाये। 24 अप्रैल रात 3 बजे मैंने कमलनाथ जी को फोन किया कमलनाथ जी ने 5 मिनट बाद काल बैक किया उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने कहा ग्वालियर संकट में है क्योंकि यहां ऑक्सीजन की कमी है। एक टैंकर आ रहा था उसका इटावा के पास एक्सीडेंट हो गया, अब वह समय पर नही पहुंच पा रहा है। उसी दिन भाजपा के नेता राजकुमार बंसल की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई। लोग मर रहे थे। कलेक्टर और हम लोग ऑक्सीजन प्लांट के अंदर खड़े थे। मैंने कमलनाथ जी से कहा कि आपसे विनती है कि कैसे भी करके आयोनेकस से ऑक्सीजन सप्लाई करवा दीजिये। (आयोनेकस पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं) आप उनसे बात कीजिए। ग्वालियर पर संकट के बादल गहरा रहे हैं आप संकटमोचक बनकर हम ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। साहब का रात में ही 3:30 दुबारा फोन आया और उन्होंने कहा कि ग्वालियर में मैं आयोनेकश टैंकर भिजवा रहा हूँ, वह ग्वालियर पहली प्राथमिकता पर पहुंचेगा। 24 घण्टे का समय दिजिये। ग्वालियर में एक टैंकर एक्ससेज में आ जायेगा जिससे ऑक्सीजन की दिक्कत नही आयेगी। प्रात: 8:30 पर फिर साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि टैंकर रवाना हो गया है। और उन्होंने टैंकर का नंबर भेज दिया। आप टैंकर की हर जगह मॉनिटरिंग करो। प्रशासन को बोलो कि ग्रीन कॉरिडोर बना दे। ताकि ऑक्सीजन का टैंकर जल्दी पहुंच जाये। और उन्होंने शक्ति से कहा कि प्रवीण यह समय श्रेय लेने व राजनीति करने का नही है। लोगों की जान बचाने का समय है। उन्होंने कहा कि टैंकर का वाहन चालक चाय भी नही पीता है ताकि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच जाये। अपने को टैंकर को लेकर कोई शोरशराबा नही करना है। जैसे इंदौर में टैंकर खड़ा करके फोटो खिचवाचे रहे। तीन घण्टे तक टैंकर को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खड़ा करके रखा। कमलनाथ ने कहा कि एक मिनट का समय भी व्यर्थ न गंवाए। लोगों को जान कीमती है उन्हें जल्दी ऑक्सीजन मिलना चाहिए। 24 अप्रेल से 01 मई तक लगातार साहब (कमलनाथ जी) ग्वालियर की मॉनिटरिंग करते रहे। कही इंजेक्शन व ऑक्सीजन की कमी तो नही हो रही है। कमलनाथ जी तो मसीहा है। मुझे दु:ख है कि इनसे बहुत बाद संपर्क में आया।

को ऑक्सीजन मास्क लगाने जैसे गंभीर वीडियो सामने आए हैं। ऐसे में प्राणदाता ही इस समय प्राण लेने में लगे हुए हैं। इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रयासों की सराहना करना होगी कि वो खुद दिन रात एक

Scanned with CamScanner

जनता की राय कमलनाथ के बारे में

आज जरूरत के वक्त में फिर माननीय नकुलनाथ जी कमलनाथ जी काम आए। बाजार में पैसा चला। न शासन प्रशासन काम आया। बस एक नेता कमलनाथ नाम ही काफी है। गर्व है मैं ऐसे नेता के लिए दिन रात लड़ता हूँ। जो लोगों का जीवन बचाने के लिए कोई कसर नही छोड़ रहे हैं। आज माननीय नकुलनाथ जी द्वारा हमारे संबंधित परिवार के सदस्य को रेमडीसिविर इंजेक्शन उपलबध कराई गई।

नीतेश उसरेठे

भाई साहब आपने हमारे परिवार के लिए जो काम किया है मैं और मेरा परिवार इस एहसान को कभी नहीं भुला पाएंगे। जो इंजेक्शन आपने इतने सरलता से हमको उपलब्ध करा दिए, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। माननीय कमलनाथ और नकुल नाथ ने हमारे छिंदवाड़ा के लिए जो भी काम किए हैं वह अतुलनीय है और आज इस परीक्षा की घड़ी में जब पूरा छिंदवाड़ा परेशान हैं तो उन्होंने जो चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई है उसकी तो बात ही अलग है। मैं एक बार फिर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और जिंदगी में कभी भी आपका यह एहसान नहीं भूलूंगी। धन्यवाद।

नीना मदन

आज हमारे आदरणीय छिंन्दवाड़ा सांसद माननीय नकुलनाथ जी के द्वारा मुझे मेरी नानी के लिए प्राण रक्षक इंजेक्शन प्राप्त हुआ। आपका सहृदय आभारी हूँ।

विनय साहू

करके लगातार प्रदेश में व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पूरी पूरी ताकत के साथ मरीजों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड दिलाने की व्यवस्था में जुटे हैं। ताकि प्रदेश में अस्पतालों की गैलरी, पार्क, पार्किंग आदि स्थानों पर बैठकर इलाज करवाने को मजबूर हैं। यह एक ऐसा समय है जब मुख्यमंत्री से निपटारा करना सिर्फ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। बल्कि उस हर प्रभावशाली व्यक्ति की है जो मध्य प्रदेश का निवासी है। फिर चाहे वो राजनेता हो, फिल्म अभिनेता हो, धार्मिक केंद्र संचालन कर्ता, या फिर व्यापारी। इन सभी से बातचीत कर मुख्यमंत्री को एक विशेष प्लानिंग करने की आवश्यकता है जिससे कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाई जा सके और दर-बदर इलाज के लिए परेशान होते लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े और उन्हें एक जगह स्थाई इलाज मिल सके। आखिरकार यदि प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगती है और लोगों को इलाज और सुविधाएं बेहतर ढंग से मिलती है तो इसमें वाहवाही तो प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की ही होगी। मध्य प्रदेश के

सरकार के कई मंत्रियों ने दिखाई अमानवीयता

कोरोना को स्थिर किया जा सके और मरने वाले मरीजों की संख्या में लगाम लगाई जा सके।

आलम यह है कि कोई बेड पर इलाज करवा रहा है तो कोई मजबूरन शिवराज सिंह चौहान को भाजपा, सरकार और पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और एक सर्वदलीय बैठक कर इस समस्या के निवारण की योजना बनानी चाहिए। निश्चित ही कोरोना की इस भयावह समस्या लिए यह एक ऐसा समय है जब शिवराज सिंह चौहान को पार्टी और सरकार से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। ऐसे में उन्हें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से बातचीत कर भी हल

Scanned with CamScanner

दमोह विधानसभा क्षेत्र का उप-चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों था?

यह एक ऐसा सवाल है जो मध्यप्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों को परेशान कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि भाजपा का प्रदेश संगठन और पूरी सरकार इस एक सीट को लेकर हलकान हुई जा रही थी। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाया हुआ था। सरकार और इसके मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की जबर्दस्त किरकिरी हो रही है और वाकई लोग बेहद परेशान हैं। इसलिए सरकार की छवि में तेज़ी से गिरावट हो रही है। यहाँ तक कि भाजपा और शिवराज को निजी तौर पर पसंद करने वाले लोग भी अब यह कहने लगे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जितना सत्ता लोभी इंसान नहीं देखा। कोरोना ने दूसरी लहर ने पिछले साल के तमाम घटनाम को लोगों के दिल दिमाग में फिर से ताज़ा कर दिया है। एक समय तक हिंदुस्तान में कोरोना की दस्तक के लिए भले ही मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के नाटकीय घटनाक्रम को जिम्मेदार मनाने से बचते रहे हों, लेकिन वह भी खुलकर इस बात का इज़हार करने लगे हैं कि शिवराज की सत्ता की हवस ने पूरे देश को कोरोना के अथाह संकट में डाला था और एक साल बाद भी इन्होंने अपनी गलतियों से कोई सीख नहीं ली।

चुनाव हैं जहां, कोरोना नहीं आता वहां...

ढूंढना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ भी देश के नामचीन व्यापारी वर्ग में अच्छी पैठ रखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबंध सीधे प्रदेश से है। वे यहां से राज्यसभा सांसद भी हैं। ऐसे में उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य सरकार की आगे आकर मदद करें। उन्हें चाहिए कि ग्वालियर सहित राजधानी भोपाल में या फिर इंदौर में अपने खर्च पर आईसोलेशन सेंटर तैयार करवाए ताकि प्रदेश में हो रही लगातार बेड की समस्या को दूर किया जा सके। आखिरकार सिंधिया ने अपनी मर्जी अनुसार अपने तीन लोगों को महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनवाया और यह तीनों ही मंत्री अपने पोर्टफोलियो में पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। इन मंत्रियों का पूरा ध्यान केवल विभागों से बजट को हेरफेर कर पैसा खाने में लग रहा है। राजधानी भोपाल जैसी स्थान पर करूणाधाम आश्रम जैसा

Scanned with CamScanner

फिर संकटमोचक बने कैलाश विजयवर्गीय

जब प्रदेश में कोरोना का कहर चल रहा था उस समय बीजेपी महासचिव विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में थे, लेकिन बंगाल में रहते हुए उन्हें मध्यप्रदेश की चिंता थी। इसी बीच वह समय-समय पर इंदौर आते रहे और कोरोना की स्थिति से अवगत होते रहे। इसके साथ ही उन्होंने अपने स्तर पर आक्सीजन, रेमडीसिवर इंजेक्शन जैसी दवाओं की व्यवस्था की। इंदौर में तो उन्होंने स्थिति को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल के चुनाव सम्पन्न होने के बाद क्यों न कैलाश विजयवर्गीय को मध्यप्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। खासकर कोरोनाकाल में तो विजयवर्गीय का मध्यप्रदेश में रहना बहुत ही आवश्यक है। सभी जानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का मध्यप्रदेश से खास लगाव है। संकट के इस दौर में उनका प्रदेश में सक्रिय रहना राज्य के हित में होगा।

कोरोना महामारी का कहर

सेवाधाम चल रहा है। जहां आए दिन गुरु सुदेश शांडिल्य महाराज सैकड़ों लोगों को भोजन कराने का काम करते हैं। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री शांडिल्य महाराज से बातचीत कर इसका विस्तार करें तो कम से कम इलाज के लिए अस्पतालों में पड़े भूखे परिजनों को दो -वक्त का खाना तो मिल सकेगा। मध्य प्रदेश ने बॉलीवुड को कई नामचीन चेहरे दिए। इनमें जया बच्चन, प्रकाश झा, आशुतोष राणा, गोविंद नामदेव, दिव्यांका त्रिपाठी दाहिया, मुकेश तिवारी, को सोनू सूद से सीख लेना चाहिए। बीते वर्ष सोनू सूद ने महाराष्ट्र से अपने-अपने घरों की ओर से जाने वाले लाखों लोगों की मदद की। ऐसे में इन अभिनेता-अभिनेत्रियों को भी आगे बढ़कर सरकार से स्वयं बात करनी चाहिए और इस आपदा के समय में लोगों की मदद करने को आगे बढ़ना चाहिए।

किसी संवेदनशील व्यक्ति को सौंपे जिम्मेदारी

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी जनता के इलाज की व्यवस्था करवाने के बजाय पिछले एक महीने से भी अधिक समय से नदारद है। लोगों ने जब सोशल मीडिया पर उनके गुमशुदगी संबंधी मैसेज चलाने शुरू किए तो मालूम चला कि मंत्री जी दमोह उपचुनाव में प्रचार प्रसार में जुटे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य

Scanned with CamScanner

कोरोना की चुनौती से मिलकर लड़ेंगे - विश्वास सारंग

(फील्ड पर रहकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं विश्वास सारंग)

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हालात कठिन हैं, बेकाबू नहीं। ये हमारे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ी चुनौती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना महामारी मध्यप्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार पूरी ताकत से व्यवस्था बनाने में जुटी है। महामारी में हर व्यवस्था छोटी लगती है। लेकिन हम एकजुटता के साथ कोरोना से जंग जीतेंगे। बेकाबू हालात कहना ठीक नहीं है। चुनौतियां हैं। ये चुनौती सिर्फ मध्यप्रदेश के लिए नहीं हैं, पूरे देश के लिए है। ऑक्सीजन के निर्माण की एक लिमिटेशन है। रेमडेसिविर के मामले में भी यही स्थिति है। ये बीमारी नहीं हैं, ये महामारी है। महामारी में हमें हर व्यवस्था छोटी लगती है। आज की डेट में जितनी हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, उतनी हम आपूर्ति कर पा रहे हैं। हम हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले हैं। इस पर काम भी शुरु हो गया है। कुछ इस महीने में शुरु कर देंगें, कुछ अगले महीने में शुरु कर देंगे। तीन महीने में हम हर जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन प्लांट शुरु कर देंगे। केवल इंडस्ट्रीज नहीं। ऑक्सीजन के सभी वैकल्पिक उपायों पर हम विचार कर रहे हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले सभी बिस्तरों पर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर लगाने की योजना है। चुनौतियां हैं, कमी नहीं बोलना चाहिए। हर चीज की एक लिमिट है। पूरे देश में डॉक्टर कम हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई थी, कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ की हम पेरेलल ट्रेनिंग कर रहे हैं। उस फोर्स को हम तैयार कर रहे हैं। चुनौतियों का हम भरपूर सामना कर रहे हैं। हम इस पर जीत हासिल करेंगे। जो कोरोना की जंग में फ्रंट पर आकर काम करे, वो कोरोना वॉरियर है।जो अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाए, वो कोरोना वॉरियर है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और ऐसी हमारी कई पुरानी पद्धतियां हैं, जो लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। वो निश्चित रूप से कारगर है। काढ़े का हमने मुफ्त में वितरण किया है। फिर से हम वितरण कर रहे हैं। अभी हमने नया कार्यक्रम शुरु किया है योग से निरोग। योग, ध्यान, आध्यात्म हमारी पुरानी पद्धतियां हैं। जो मानसिक रूप से भी व्यक्ति को सुदृढ़ बनाते हैं। कोरोना में व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं मानसिक रूप से भी टूटता है। ये पद्धतियां मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। हम इनका उपयोग कर रहे हैं। हमने सुनिश्चित किया है कि कोरोना वार्ड में मनोचिकित्सक जाएं और मरीजों की काउंसलिंग करें। इस महामारी में मरीज का मनोबल टूटता है। सांस कम आती है, तो उसे लगता है वो जाने वाला है। ये सीधा सीधा व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। इसलिए हमने मनोचिकित्सकों की ड्यूटी लगाई है। लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, लोग रामायण देखें। लोग इस तरह मानसिक रूप से मजबूत हों। कोरोना कर्फ्यू पर उन्होंने कहा कि इसका मकसद ये है कि हम स्वयं अनुशासित होकर इसका पालन करें। हम टोटल लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था भी देखनी है, रोज कमाने खाने वालों की भी सोचना है।अगर हम कोरोना चेन को नहीं तोड़ेंगे, तो किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। मैंने भोपाल में विभिन्न लोगों से वीडियो के जरिए बातचीत की। मैंने सबसे निवेदन किया है कि हम स्वयं से अपना कर्फ्यू लागू करें। कोरोना को लड़ाई को जीतना है, तो केवल संक्रमण की चेन को तोड़ना है।

विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी छोड़ जो मंत्री जनता के इलाज की चिंता को छोड़ चुनाव प्रचार प्रसार में जुट जाए तो भला ऐसे व्यक्ति को इस विभाग के मंत्री पद की जिम्मेदारी देना कितना सही है। सिंधिया के खेमे के इन लापरवाह विधायकों को इतने महत्वपूर्ण

Scanned with CamScanner

पिता के नक्शे कदम पर आकाश विजयवर्गीय

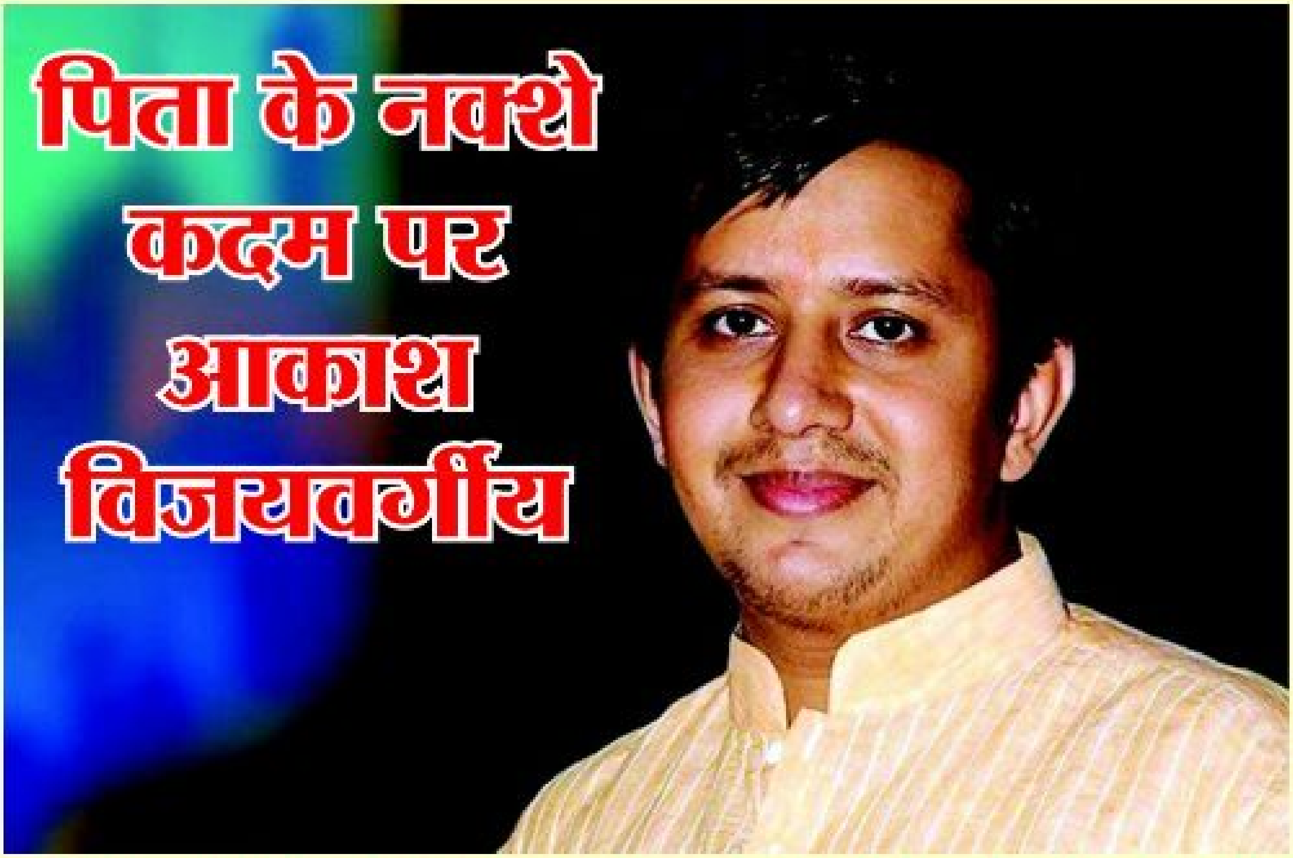

इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय समाजसेवा में अपने पिता कैलाश विजयवर्गीय के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच आकाश ने कोरोना गाइडलाईन के तहत कार्य करने की अपील करने के साथ साथ प्रशासन का पूरा साथ दिया। लोगों की मदद भी कर रहे हैं। जिसको जैसी जरूरत वैसे मदद कर रहे हैं। गौरतलब है कि एमपी के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के खिलाफ अब जन जागरण का अनूठा अभियान चलाया जा रहा है। जिसके चलते सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे शहर भर में गाड़ियों के सायरन बजाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और कोरोना से बचाव की अपील की जा रही है। इंदौर के प्रशासन के साथ बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने शहर के राजवाड़ा क्षेत्र में सायरन बजाने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के अभियान की शुरुआत की। इंदौर में हर दिन कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और नए मामले तेजी से आ रहे हैं। संक्रमित लोगों की संख्या रोज 300 से 400 तक पहुंच रही है। इंदौर में लगभग हर दिन औसत 380 तो प्रदेश में 1500 केसेज सामने आ रहे हैं। इसकी वजह संक्रमण के प्रति लोगों की लगातार लापरवाही है। ना तो लोग मास्क लगाने को लेकर गंभीर हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को तैयार हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सायरन बजाने के अभियान की शुरुआत के साथ ही इंदौर में शहर के तमाम अधिकारियों ने विधायक आकाश विजयवर्गीय के साथ मिलकर सायरन बजाया और अभियान की शुरुआत की।

पोर्टफोलियो दिए ही क्यों जिसको वो संभालने में पूरी तरह से विफल है। फिर चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत हो, तुलसीराम सिलावट हो या फिर खुद डॉ. प्रभुराम चौधरी। इन तीनों ही लोगों को सिंधिया के दवाब में आकर मुख्यमंत्री ने इतने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिए हैं जिन्हें ये अब तक संभालने में पूरी तरह से नकारे ही साबित हुए है, इसका सबसे ताजा उदाहरण है प्रभुराम चौधरी। शिवराज सरकार को तत्काल प्रभाव से डॉ. प्रभुराम चौधरी से इस जिम्मेदारी को वापस लेते हुए किसी संवेदनशील व्यक्ति को यह पोर्टफोलियो देना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता के इलाज की समुचित व्यवस्था समय रहते की जा सके।

Scanned with CamScanner

सिंधिया की तरह ही रणछोड़ साबित हुए प्रभुराम चौधरी

ये हैं प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी। जो कहने को तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। लेकिन इन्हें पता ही नही रहता कि कोरोना काल में किस दवा की जरूरत है और किस दवा की किल्लत है। हमने देखा है कि प्रदेश के आक्सीजन की और इंजेक्शन की किल्लत रही लेकिन इन्होंने हमेशा कहा कि इन दोनों की भरपूर मात्रा है। जिसके लिए इनकी काफी किरकिरी भी हुई थी। कोरोना जैसी महामारी में भी यह हमेशा नदारद ही रहे हैं। इन जैसे मंत्रियों के कारण ही प्रदेश में हालात खराब हो रहे हैं।

आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च से अब तक प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में 31 मार्च को मात्र संक्रमित मरीज थे जो 14 अप्रैल को बढ़कर 874 हो गए। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वायरस के करीब 80 प्रतिशत मरीज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एवं इंदौर में हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या करीब 7.26 करोड़ है। कोरोना महामारी ने जन-स्वास्थ्य को तो प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया ही, प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी।

आज फिर यही स्थिति है। लोगों के रोजगार छिन गए। खाने पीने लाले पडे हैं। कोरोना के हालात बिगडते जा रहे हैं।

सरकार के बस से बाहर जा रहे हैं। सीएम दिनरात तो लगे हैं लेकिन सरकार के अन्य सहयोगियों का साथ न मिलने से स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन सवाल फिर उठता है कि आखिर अकेले शिवराज कहां तक स्थितियों को संभालें रहेंगे। आखिर सरकार के अन्य सहयोगियों को भी उनका साथ देना चाहिए। यह बात सच है कि आज की स्थिति में जितने संवेदनशील शिवराज हैं उतने उनके मंत्री नहीं है। वैसा सहयोग नहीं कर रहे जितना करना चाहिए।

बेकाबू होते देश के हालात

देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर की सुनामी आ गई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। भारत की वर्तमान स्थिति पर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का बयान आया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। भारत की स्थिति अब काफी नाजुक हो गई है। कई देशों को अभी भी कोरोना के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन

Scanned with CamScanner

कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा

खुद को शहंशाह मानने वाले प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा अपनी करतूतों को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल साहब का ग्वालियर के डबरा स्टेशन के पास का एक वीडियो सामने आया है जहां ये रेलवे के नियमों की धजियां उड़ाते दिखाई दिए। गृहमंत्री साहब के ठाठ इतने कि स्टेशन से पटरी पर उतरने के लिए वहां मौजूद रेलवे कर्मचारियों द्वारा इनके लिए बीच पटरी पर बैंच रखी गई। जिस पर पैर रखकर साहब प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे और फिर चल दिए। साहब के कारनामे यहीं नही रूकते इस दौरान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। अपनी आदत से मजबूर नरोत्तम मिश्रा एक तरफ रोज कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए से मास्क पहनने की लोगों से अपील करते हैं और खुद नियमों की धजियां उडा रहे है। यह पहला अवसर नहीं है जब नरोत्तम मिश्रा बिना मास्क पहने लोगों के बीच में गए हो। इससे पहले भी वे मास्क के बिना ही पूरे प्रदेश में घूमते। बाद में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फटकार लगाई तो वे मास्क पहनने लगे। लेकिन डबरा में सोशल डिस्टेसिंग, कोविड गाइडलाइन सहित रेलवे के नियमों की जो धजियां उड़ाई गई है उससे साहब फिर चर्चा में है। सूत्रों की मानें तो नरोत्तम मिश्रा की यह सोची समझी चाल है। दरअसल वे चाहते है कि मीडिया उन पर फोकस करे और वे टेलीविजन, अखबारों सहित सोशल मीडिया पर छाए रहे। इसलिए वे जानबूझकर भी इस तरह से नियमों की धजियां उड़ाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। जहां प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या मे तेजी से इजाफा हो रहा है उसे लेकर न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद भी चिंतित है। वे लगातार अफसरों के साथ बैठकर कोविड संक्रमण को रोकने के लिए नियमावली तैयार कर रहे हैं और लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वे कोविड नियमों का पालन करें। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की जिद के आगे भला किसकी चली है। खुद मुख्यमंत्री भी अपने कई मंत्रियों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन मंत्री मुख्यमंत्री की बात को सिरे नकार देते है और करते वहीं है जो उन्हें करना है। इस बात का ताजा उदाहरण है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की लापरवाही।

भारत में स्थिति दिल दहलाने वाली है। भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। देश में कोरोना के नए केस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भारत और दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कुल केस 14 करोड़ के पार पहुंच गए हैं और 50 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं भारत में इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कुल मामले अब डेढ़ करोड़ के पास पहुंच गए हैं और कोरोना के कुल मौतों का आंकड़ा दो लाख के आंकड़े के पार पहुंच गया है। भारत के संक्रमण के आंकड़ों ने अब अमरीका तथा ब्राजील जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनका इस महामारी के निपटने के मामले में प्रदर्शन अब तक सबसे खराब माना जाता था। दूसरी लहर के लिए न तो खुद केंद्र ने

Scanned with CamScanner

क्या मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण से मौतों के आंकड़े छुपा रही है सरकार?

क्या मध्यप्रदेश में कोरोना से मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकारी आंकड़े और श्मशान पहुंच रहे शवों की संख्या में गंभीर विसंगतियां हैं। राजधानी भोपाल में अकेले भदभदा विश्राम घाट पर ही सोमवार शाम 6 बजे तक 37 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, पांच शवों को कब्रिस्तान में दफनाया गया। दूसरी ओर सरकार की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में पूरे राज्य में 37 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया गया है। भदभदा विश्रामगृह में अपने बड़े भाई के शव के अंतिम संस्कार के आए बीएन पांडे को इतनी लाशें देखकर भोपाल गैस कांड का खौफनाक मंज़र याद आ गया। उन्होंने कहा कि 1984 में गैस कांड के पीड़ितों के बाद ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है, उस वक्त तो मैं नवीं में पढ़ता था। मेरे सामने 2-3 घंटों में 30-40 लाशें जल चुकी हैं। यह और बात है कि सरकारी बुलेटिन में पूरे राज्य में 37 लोगों की कोरोना से मौत की बात लिखी है, जितनी एक श्मशान में जलाई गई। खैर। यहां कोविड मरीजों के शव को नगर निगम की गाड़ी सीधे अस्पताल से विश्राम घाट के पिछले गेट पर लेकर आती है। यहां एक अलग व्यवस्था बनाई गई है ताकि सामान्य अंतिम संस्कार वाले लोग संक्रमण से सुरक्षित रहें। लेकिन जो अपनों के अंतिम दर्शन करने आए, वो भीड़ से परेशान हो गए। अपने बहनोई के अंतिम संस्कार के लिए आए संतोष रघुवंशी ने कहा 3-4 घंटे से बैठे हैं, चारों तरफ लाशें जल रही हैं क्रिया कर्म कर ही नहीं सकते, जितनी लाशें हैं उसके हिसाब से यहां जगह ही नहीं है। अव्यवस्था एक बात है, लेकिन मौत के आंकड़ों में असमानता दूसरी।

आठ अप्रैल को भदभदा में 31 शवों सहित शहर में 41 शवों का कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया, जबकि उस दिन सरकारी मेडिकल बुलेटिन में पूरे प्रदेश में 27 लोगों की संक्रमण से मौत की बात कही गई। 9 अप्रैल को 35, सरकारी बुलेटिन में 23 लोगों की मौत। 10 अप्रैल को 56, सरकारी बुलेटिन में 24 लोगों की मौत। 11 अप्रैल को 68, सरकारी बुलेटिन में 24 लोगों की मौत और 12 अप्रैल को शहर में 59 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकारी बुलेटिन में पूरे राव में 37 लोगों की मौत बताई गई। हालांकि सरकार का कहना है कि वो कोई आंकड़े नहीं छिपा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा सरकार की कोई मंशा नहीं है कि मृत्यु के आंकड़े को छिपाया जाए ऐसा करके हमें कोई अवॉर्ड नहीं मिलने वाला। पिछले सप्ताह अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी कम पड़ जाने की बात भी सामने आई थी। विश्रामगृह में काम करने वाले रईस खान ने हमें बताया कि वहां रोज़ 100-150 क्विंटल लकड़ी काटी जा रही है, बीच में कमी हो रही थी लेकिन अब ठीक है। रोज़ाना वहां 40-45 शव आ रहे हैं। इन श्मशानों में काम करने वाले कर्मचारी भी अब थकने लगे हैं, हाथों में छाले पड़ गये हैं, कइयों को चोट लगी है। यहां काम करने वाले प्रदीप कनौजिया कहते हैं अब यहां ज्यादा शव आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है थकान हो रही है, डर लगता था पहले, अब भी शव के साथ पब्लिक ज्यादा आ रही है, भीड़ हो जाती है, पानी पिये जाते हैं खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। सरकारी आंकड़ों में बाजीगरी के बीच, एक हकीकत ये है कि जलती चिताओं के बीच बेहद नजदीक दूसरी चिताएं सजाई जा रही हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है, वो भी तब जब एक चिता ठंडी होने से पहले ही दूसरे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है।

कोई तैयारी की और न राज्यों से कोई तैयारी करायी। वह तो यही माने बैठी थी कि महामारी खत्म हो गयी है। देश में कोविड-19 महामारी के थमने के कोई आसार दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अप्रैल के तीसरे हफ्ते के आखिर में चौबीस घंटे में नये केसों का

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश के महानगरों के बाद गांव में पैर फैला रहा कोरोना संक्रमण

कोरोना संक्रमण प्रदेश में पूरी तरह से अपनी जड़े फैला चुका है। अभी तक जहां सिर्फ प्रदेश के बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण का जाल बिछा हुआ था वहीं अब यह जाल धीरे-धीरे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की तरफ बढ़ रहा है। और यदि ऐसा हुआ तो आने वाला समय मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। कोविड महामारी की दूसरी लहर अब गांवों में भी बरपा रही है कहर, इसका ताजा उदाहरण इंदौर के 35 किमी दूर कुडाना गांव के होली चौक पर पसरा सन्नाटा इस बात का गवाह है कि गांव में कुछ ठीक नही है। 40 हजार की आबादी वाले छोटे से गांव मे 60 में ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके है एवं 15 की मौत भी हो गई है। इसके बावजूद सरकार और उनके नुमाइंदे उतने चिंतित नही है। यह तो इंदौर जैसे बड़े शहर के पास गांव की स्थिति है। ग्रामीण दूर दराज इलाके में स्थिति बद से बदतर है। लोग बिना टेस्टिंग और मेडिकल सुविधाओं के अभाव

आंकड़ा तीन लाख से ऊपर जा चुका था। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। आईसीयू की कमी है। यहां तक कि ऑक्सीजन की भी कमी हो गयी है। नतीजा यह कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मुर्दाघर, श्मशान और कब्रिस्तान लाशों से पटे पड़े हैं। भारत के संक्रमण के आंकड़ों ने अब अमरीका तथा ब्राजील जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनका इस महामारी के निपटने के मामले में

Scanned with CamScanner

में दम तोड़ रहे है। हाल ही में शिवराज जी ने किसान सम्मा न निधि में राशि भुगतान का ऐलान किया है सम्मान निधि किसानों को तब मिलेगी जब वह जीवित रहेगा राजनीति के लिए ऐलान करना ठीक नही है युद्ध स्तर पर सिर्फ कोरोना महामारी से निपटने की तैयारी करें। वर्तमान गांव में वेंटिलेटर, आक्सीजन, एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ की व्यवस्थाओं पर ध्यान दें जान है तो जहान है को सर्वमान्य मानकर ग्रामीण इलाकों की भयावहता को भांप कर वर्तमान में सही निर्णय ले। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ द्वारा तीसरी लहर का प्रकोप भी जल्द ही बताया जा रहा है उसे भी संज्ञान में रखते हुए मेडिकल व्यवस्थाओं को मजबूत करें क्योंकि ग्रामीण इलाकों में महामारी पर अंकुश लगा पाना असंभव होगा।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कोरोना संक्रमण को लेकर क्या तैयारियां है उसकी स्थिति दूसरी लहर में सामने आ चुकी है। हर तरफ लाशों का ढेर, प्रतिदिन मरते सैकड़ों लोग, अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी यह सब स्वास्थ्य विभाग की नाकामी का सबूत है। हाल ही में देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के. विजय राघवन के बयान के बाद स्थिति और गंभीर होती दिखाई दे रही है। राघवन ने स्पष्ट सरकार को चेतावनी दी है कि जिस तरह से देश में संक्रमण फैला हुआ है उस स्थिति को देखते हुए तीसरी लहर आना लाजमी है और अगर ऐसा हुआ तो वो दृश्य बहुत ही भयावह होने वाला है। क्योंकि कोरोना संक्रमण ने पहली लहर में बुर्जगों को अपना निशाना बनाया दूसरी लहर में युवा शक्ति को और तीसरी लहर में बच्चों का शिकार बना सकता है। ऐसे में शिवराज सरकार को प्रदेश की स्थिति को अभी से तुरंत काबू में करने के लिए प्लान बना लेना चाहिए ताकि तीसरी लहर से प्रदेश की जनता को बचाया जा सके।

जल्द से जल्द हो लोगों का वैक्सीनेशन

एक बात समझ के परे है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण की घोषणा की थी तो प्रदेश सरकार को अपने यहां वैक्सीनेशन की स्थिति से उनसे परिचित क्यों नहीं कराया। यदि समय रहते सरकार समझदारी दिखाती तो आज बड़ी संख्या में प्रदेश के लोगों का वैक्सीनेशन हो जाता है। अब सिर्फ सरकार की कोशिश यह होनी चाहिए कि जल्द से जल्द लोगों का वैक्सीनेशन करें, इसलिए जब तक सभी का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक प्रदेश में लॉकडाउन को यथावत रखने पर विचार करना चहिए।

युवाओं की मृत्यु दु:खद

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा युवाओं को अपना शिकार बनाया। यह न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में यही स्थिति देखने को मिली। इन सबका एक बड़ा कारण है राज्य सरकारो का संक्रमण की तरफ से ध्यान हटना। दरअसल संक्रमण की पहली लहर के बाद राज्य सरकारो ने संक्रमण से बचाव संबंधी तमाम सुविधाओं को विकसित करने के बजाय सिर्फ चुनावों पर ध्यान दिया। यही वजह है कि जब संक्रमण की दूसरी लहर आई तो उसने देश के युवाओं को अपने चपेट में लिया। 131 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 60 प्रतिशत युवा हैं जिनमें बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता है। लेकिन सरकारों की आलस्यता के कारण आज युवा मर रहा है। कई घर बिना बेटे, बिना पिता, बिना भाई के हो गए और सरकार सिर्फ आंकड़े छिपाने में व्यस्त रही।

आगे की क्या है तैयारी

देखा जाए तो मध्यप्रदेश में तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार की कोई खास कोशिशे नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि संक्रमण इस बार अपना शिकार बच्चों को बनाएगा। इसका मतलब है कि देश के बच्चों की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि सरकार के पास न तो इससे बचाव के लिए ऐसा कोई सटीक प्लान नहीं जिससे बच्चों की जिंदगी को बचाई जा सके। देश में अब तक बच्चों की वैक्सीन पर कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है यह भी एक चिंता का विषय है।

प्रदर्शन अब तक सबसे खराब माना जाता था। इससे भी यादा चिंताजनक बात यह है कि अब टेस्ट किए जाने वाले हरेक पांच लोगों में से एक व्यक्ति बल्कि उससे भी ज्यादा संक्रमित लोग निकल रहे हे। यह चंद महीने पहले के अनुपात से चार गुने से भी ज्यादा है। यह इसका इशारा करता है कि वास्तव में संक्रमितों की संख्या, आंकड़ों में जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा होगी।

Scanned with CamScanner

सरकारी आंकड़ों में कोरोना से सिर्फ 109 की मौत, लेकिन अप्रैल में हुए 2500 अंतिम संस्कार

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भोपाल में अप्रैल महीने में कोविड-19 से हुई मौतों के सरकारी आंकड़े और इसी अवधि में शमशान घाट और कब्रिस्तान में हुए अंतिम संस्कार के आंकड़ों के बीच काफी अंतर है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़ों और जमीनी स्थिति में काफी अंतर है। भोपाल प्रशासन की माने तो अप्रैल महीने में जिले कोरोना वायरस से 109 मौतें दर्ज की गईं लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तान का आंकड़ा कुछ और ही बताता है। कोविड-19 मरीजों के लिए जिले में तीन शमशान घाट और एक कब्रिस्तान हैं और वहां से जुटाए गए आंकड़ों का कहना है कि 1-30 अप्रैल तक जिले में 109 कोविड मृतकों के अलावा 2,567 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं इन चारों जगहों के कर्मचारियों का कहना है कि इस अवधि के दौरान 1,273 गैर कोविड मरीजों का भी अंतिम संस्कार किया गया है। भोपाल में छह शमशान घाट और चार कब्रिस्तान हैं। जिसमें चार शमशान घाट और एक कब्रिस्तान कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किया हुआ है। कब्रिस्तान और शमशान के अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि शवों की भीड़ से निपटने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। वहां काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि हमारे शमशान घाट की हालत बेहद खराब हो गई है। यहां जगह-जगह पर पीपीई किट और दस्ताने पड़े मिलते हैं। उनकी मांग है कि नगर निगम इन जगहों को कम से कम सैनिटाइज और साफ करे, ताकि दूसरे शवों को जलाने में आसानी हो। इसके अलावा उनकी शिकायत है कि शमशान घाटों और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई है और काम करने वाले लोग भी कम हैं। शवों के लिए जमीन खोदने वाले लड़के अब थक चुके हैं। शवों की संख्या बहुत ज्यादा आती है। वहीं प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी का कहना है कि प्रदेश की ओर से मृतकों का आंकड़ा नहीं छुपाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ ऐसे मामले जरूर हैं, जो कंफर्म कोविड मरीज नहीं है, संदिग्ध हैं लेकिन उनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए हैं।

इस महामारी से निपटने में केंद्र सरकार ने कहां गलती की है? यह सरकार उस दूसरी लहर के लिए तैयार ही नहीं थी, जिसने अब से करीब एक महीने पहले तेजी से उठना शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार और उसके विशेषज्ञ तो यह माने बैठे थे कि 2021 के फरवरी तक कोविड-19 की महामारी खत्म हो जाएगी और उसके बाद देश सामान्य हालात पर लौट आएगा। मोदी सरकार विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के तथाकथित सुपरमॉडल के अपने प्रचार को ही सच मान बैठी थी और महामारी से लड़ने में अपनी भारी कामयाबी पर अपनी पीठ ठोकने में लगी हुई थी। वह जब अपनी इस कामयाबी को विधानसभा चुनाव के ताजा चश्में अपनी चुनावी जीत में तब्दील करने की तैयारियों में लगी हुई थी, तभी दूसरी लहर ने देश को

कमलनाथ का आरोप, गांवों में कोरोना से बदतर हालात, नजरअंदाज कर रही सरकार

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होने की बात कहते हुए सरकार पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह हो चली है और इस पूरे मामले में सरकार तत्काल संज्ञान लेकर इसकी पूरी जांच करवाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं व संसाधन बढ़ाने का काम युद्धस्तर पर किया जाए। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि अब तक उत्तरप्रदेश और बिहार में गंगा नदी में बहते शवों की तस्वीरें हम देख रहे थे और अब मध्यप्रदेश में भी पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के नंदनपुर गांव में रुंझ नदी में छह बहते हुए शवों की दर्दनाक तस्वीरें सामने आयी हैं। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताया है।

अपनी चपेट में ले लिया। बहरहाल, जैसे ही संक्रमणों की संख्याएं बढ़ने लगीं, महामारी का मुकाबला करने के लिए देशव्यापी आधार पर कोई सहकारितापूर्ण योजना तैयार करने की कोशिश करने के बजाए, भाजपा ने हमले का रास्ता अख्तियार किया। केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य सरकारों को पर्याप्त प्रयास न करने के लिए दोष देना शुरू कर दिया और जनता को मास्क लगाने तथा सामाजिक दूरी का पालन करने जैसे बचाव उपायों की उपेक्षा करने का दोषी बताना शुरू कर दिया। यह इसके बावजूद था कि केंद्र सरकार तो खुद ही सार्वजनिक सभाओं, चुनाव अभियानों और कुंभ मेला जैसे विराट धार्मिक समागमों के जरिए, सामान्य हालात लौट आने के संकेत दे रही थी। इसलिए अगर जनता ने कोविड-19 की पाबंदियों के पालन में ढील दे दी थी, तो भी वह तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत सत्तापक्ष के तमाम नेता मंचों पर जो कुछ कर रहे थे, उसका अनुकरण ही कर रही थी।

कोविड-19 की पहली लहर, करीब 1 लाख दैनिक नये संक्रमणों के साथ, सितंबर के मध्य के करीब अपने शीर्ष पर पहुंची थी। इसके बाद एक महीने में ही संमणों की संख्या इससे आधी रह गयी और अक्टूबर के मध्य

छोटे-बड़े नगरों की अस्पतालों के हालात कुछ इस तरह के हैं।

Scanned with CamScanner

भोपाल में बदतर हालात, अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमितों की हालत जानने के लिए भी तरस रहे स्वजन

कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के साथ अस्पतालों में भी हालात दिनोंदिन हालात भयावह होते जा रहे हैं। आलम यह है कि अस्प ताल में भर्ती कोरोना पीड़ित मरीजों से अधिक परेशान उनके स्वजन हो रहे हैं। परिवार के सदस्यों को यह तक नहीं बताया जा रहा है कि अब मरीज की हालत कैसी है। कोविड सेंटर चिरायु अस्पताल के बाहर मरीजों के स्वजनों को परेशानी की हालत में देखा जा सकता है। दो दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर खबर आई थी कि चिरायु में एक साथ 34 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि यह अफवाह निकली। अस्पताल प्रबंधन ने भी समझदारी दिखाते हुए तत्काल स्पष्टीकरण जारी कर दिया। इस खबर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वजनों को परेशानी में डाल दिया। कई मरीज आइसीयू में भर्ती हैं, जिनके मोबाइल भी बंद हैं। किसी से बात करने की अनुमति नहीं है। पिछले साल कोरोना मरीजों से बात करना आसान था। अस्पताल के कर्मचारी भी मरीज की स्थिति के बारे में स्वजनों को आसानी से जानकारी दे देते थे। इस बार स्थिति विपरीत है। किसी को भी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। मरीजों के स्वजनों की अस्पताल के बाहर बढ़ती संख्या को देखते हुए चिरायु के बाहरी गेट पर ही बैरिकेड्स रख दिए गए हैं। अंदर जाना भी आसान नहीं रहा। कई मरीजों के स्वजन कैंटीन के शेड के नीचे ही बैठे हैं। अधिकांश मरीजों से बात करने के प्रयास कर रहे हैं। स्वजनों की चिंता यह है कि अस्पताल में प्रतिदिन कई लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो रही है। दो या तीन दिन बात नहीं होने पर परिवार के सदस्य अनहोनी से आशंकित हो जाते हैं। अस्पताल प्रबंधन इस संबंध में मीडिया से भी बात नहीं कर रहा है।

से संख्या घटती रही और फरवरी के आखिर तक और नीचे चली गयी। करीब चार महीने की इस राहत का इस्तेमाल, देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यानी अस्पतालों में बेडों की संख्या, आईसीयू सुविधाएं बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखला को ताकतवर बनाने और इसके नियम-कायदे तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए था कि अगली लहर जब आएगी, उसे कैसे संभाला जाएगा।

कोविड-19 की पहली लहर का प्रभाव कुछ राज्यों तक और उनमें भी कुछ खासतौर पर घनी आबादी वाले इलाकों तक ही सीमित था। इस बार की लहर करीब-करीब पूरे देश में फैल गयी है और समाज का बहुत बड़ा दायरा इसकी चपेट में आया है। ऐसे हालात के लिए हमने अब से महीना भर पहले तक भी तैयार क्यों नहीं की थी? आखिरकार, तब तो केसों की संख्या के बढ़ने की रफ्तार से केंद्र सरकार को आने वाले संकट की चेतावनी मिल जानी चाहिए थी। करीब महीने भर पहले जब ये खतरे के संकेत मिलने शुरू हुए थे, उसके बाद से कम से कम आक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने और उसे राज्यों तथा अस्पतालों तक पहुंचाने पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया ही जा सकता था। और

दहशत में देशवासी कोरोना को काबू करने में सरकारों की अनदेखी

Scanned with CamScanner

सरकार और प्रशासन के प्रति आम जनता का आक्रोश

वहीं ऐसे कई लोग हैं, जो इन नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं और प्रशासन द्वारा सख्ती बरते जाने पर उनसे बहस कर या हाथापाई तक उतर जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के दो अलग-अलग इलाकों के इन मामलों से संबंधित वीडियो वायरल हुए हैं। जिसमें पुलिस द्वारा मास्क लगाने को कहने और मास्क न लगाने की वजह से युवक का चालान काटा जाता है तो युवक भड़क जाता है और नेताओं के मास्क न लगाने का हवाला देता है। इस बीच वहां मौजूद जनता भी आक्रोशित हो जाती है और पुलिस के साथ हाथापाई तक नौबत आ जाती है। वहीं एक और वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें पति-पत्नी कार से जा रहे होते हैं और मास्क ना लगाने की वजह से पुलिस जब उनका चालान करने लगती है, तो पति और पत्नी दोनों बुरी तरह भड़क उठते हैं। उनका कहना होता है कि कार के अंदर हम क्यों मास्क लगाएं और वहीं बातों ही बातों में वे कभी नेताओं, तो कभी रैलियों का हवाला देते हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में मध्यप्रदेश के इंदौर से एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें पुलिस वाला एक दुकानदार को बीच रोड पर जमकर पीटता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उसने मास्क नहीं पहन रखा था और ऐसा भी कहा गया कि उसने चालान देने से मना कर दिया था। ऐसे तमाम मामले हैं, जब आम जनता पर नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरती गई और कहीं-कहीं बर्बरता भी की गई।

तभी से ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग के मुकाबले, उसे चिकित्सकीय उपयोग के लिए तैयार करने को प्राथमिकता दी जा सकती थी, जो काम अब देर हो जाने के बाद किया जा रहा है। सरकार ने ये सभी तत्काल जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए और संक्रमणों की संख्या में इतनी भारी बढ़ोतरी को संभालने की तैयारी क्यों नहीं की? ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह की नजरें पूर्व में तथा

Scanned with CamScanner

सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना संकट को लेकर अपने नेशनल प्लान की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना महामारी को एक राष्ट्रीय संकट बताते हुए कहा केंद्र से इस पर नेशनल प्लान मांगा था। जिस पर केंद्र की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले, अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये कोई आम हालात नहीं हैं, लोग मर रहे हैं। ऐसे में हम बैठकर चुपचाप ये सब नहीं देख सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चार मुद्दों पर केंद्र सरकार से मांगा था, पहला- ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने को लेकर सरकार क्या कर रही है। दूसरा- देश में कोरोना की एंटी वायरल ड्रग रेमेडिसविर जैसी दवाइयों की किल्लत पर क्या है योजना? तीसरा- सभी को टीकाकरण का प्लान और चौथा- देश में लॉकडाउन लगाने को लेकर विचार और योजना।

खासतौर पर बंगाल में चुनावी जीत पर ही गढ़ी रही हैं। दूसरी सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी चुनावी रैलियां रोके जाने के बाद ही, भाजपा को इसका एहसास हुआ कि भारी महामारी के बीचो-बीच प्रधानमंत्री के चुनावी रैलियां करते रहने से कैसी नकारात्मक छवि बन सकती है। लेकिन, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और हालात बहुत बिगड़ चुके थे।

कोरोना की दूसरी लहर में भयावह स्थिति

अस्पतालों में बेड नहीं, आक्सीजन नहीं, कैसे मिले जिंदगी

देश में कोरोना महामारी दिन-प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर पिछले साल के मुकाबले यादा घातक साबित हो रही है। भारत में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर तीन लाख के उपर पहुंच गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक उपचाराधीन मामले 20 लाख के करीब पार पहुंच गए हैं। एक तरफ जहां कई राज्यों में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन जैसे कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं देश के कई राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सरकारें खुद कोरोना को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश

Scanned with CamScanner

रेमडेसिविर दवाई की किल्लत और सरकार की नीति

देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के बाद एंटी-वायरल ड्रग रेमडेसिविर की भारी किल्लत हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के कई कारण सामने आ रहे हैं। इसमें एक कारण यह भी है कि बीते दो-तीन महीनों से इस दवा के उत्पादन में काफी कमी आ गई थी। रही सही कसर देश में कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी कर दी है। डॉक्टरों के मुताबिक रेमडेसिविर कोरोना बीमारी की अवधि कम करता है, लेकिन मौत की दर को घटा नहीं सकता। यह एक जरूरी ड्रग है और संक्रमण अधिक फैलने से लंग्स खराब होने की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से आजकल बाजार में इस दवाई की किल्लत बढ़ गई है। अगर दवाई मिल भी रही है तो काफी महंगे दामों में मिल रही है। इसलिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों इस दवाई की निर्यात पर पाबंदी लगा दी है और अब कई राज्य सरकारों ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है।

रेमडेसिविर की मांग में क्यों कमी आ गई थी

फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को मानना है कि दिसंबर 2020 के बाद से कोविड-19 के मामलों में कमी के कारण रेमडेसिविर की मांग में कमी आ गई थी। इस कारण से इस दवाई को बनाने वाली कंपनियों ने इसका उत्पादन कम कर दिया था। जनवरी और फरवरी महीने में भी उत्पादन पहले की तुलना में काफी कम हुई। अब, जबकि इसकी मांग एक बार फिर से बढ़ गई है तो कंपनियों ने उत्पादन तेज कर दी है। बता दें के रेमडेसिविर दवा की अवधि 6 से 8 महीने की होती है। डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना की पहली लहर रेमडेसिविर की मांग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर और लखनऊ जैसे महानगरों और बड़े शहरों तक सीमित थी, लेकिन दूसरी लहर में इस दवा की मांग बड़े शहर से लेकर छोटे शहरों और गांव-देहात में भी होने लगी है। इस कारण बनाने वाली कंपनी मांग के हिसाब से सप्लाई नहीं कर पा रही है।

सहित ऐसे कई राज्यों में कोरोना अपने चरम पर मौत का तांडव मचा रही है। लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। बेड उपलब्ध नहीं हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग भटक रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं लेकिन प्रशासन भी जैसे असहाय महसूस कर रही है। ऐसे में कई राज्यों ने एक बार फिर लॉकडाउन को हथियार बनाकर कोरोना से जंग शुरू कर दी

कोविड-19 की दूसरी लहर और मोदी सरकार की विफलता

35 गाँव के बीच एक अस्पताल, महीने भर में एक भी टीका नहीं लगा

है। वहीं केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को कहा जा रहा है, जिसके लिए सख्त नियम भी बनाए गए हैं। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर चालान भी किए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार लोगों को सामाजिक दूरी, मास्क लगाना अनिवार्य, भीड़-भाड़ से परहेज़, सैनिटाइज़र के उपयोग आदि शामिल हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल-कॉलेज आदि भी बंद

Scanned with CamScanner

आक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार कौन

ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर ऑक्सीजन प्लांट लगाने तक को लेकर अब बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। यह कुछ ऐसा है कि जैसे आग लगने पर कुआं खोदा जाए। अगर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। नाराजगी भरे यह शब्द किसी व्यक्ति नेता और अफसर के नहीं है। बल्कि इंसाफ का फैसला सुनाने वाले अदालतों में से एक दिल्ली उच्च न्यायालय के हैं। जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वह अगर कोई कड़वी बात भी कहेंगे तो थोड़ा उसे सलीके से कहेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट को इस तरह से अपनी राय रखनी पड़ी। कोरोना के समानांतर ऑक्सीजन संकट भी चल रहा है। अस्पताल में जाकर भी कई लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे जा रहे हैं। देश के बड़े-बड़े शहरों के बड़े-बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबर आ रही है। लोग अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाए बैठे दिख रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह पर बिस्तर और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से लोग घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं। जबकि बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों के पास ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी। लेकिन यह नहीं है। डॉक्टर खुद कहते हैं कि कैसे किसी कमरे को आईसीयू कहा जाए, जब कमरे में ना तो वेंटिलेटर की व्यवस्था है और ना ही कोई ऐसी पाइप है जिसकी मदद से ऑक्सीजन पहुंचती हो। यही हाल बड़े बड़े नामी-गिरामी प्राइवेट अस्पतालों का भी है। जो लोगों से बहुत बड़ी कीमत वसूल करते हैं। लेकिन सुविधा के नाम पर उन्होंने भी अपने अस्पताल के लिए किसी तरह ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था नहीं की है। केवल मुनाफे के सिवाय कुछ नहीं सोचा है। इन सबके बीच चूंकि सुविधाएं कम हैं, इसलिए इस आपदा में कालाबाजारी भी खूब बढ़ी है। इस कालाबाजारी में कीमतें बहुत अधिक बढ़ी हैं। तकरीबन 4500 से लेकर 5000 के बीच मिलने वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 8000 से 10000 रुपये तक मिल रहा है। एक बार रिफिल करवाने में जिस ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए 150 से लेकर 200 रुपये तक लगता था अब उसकी कीमत 800 से लेकर 1000 तक पहुंच गई है। ऑक्सीजन उत्पादन से जुड़े काम में लगे हुए लोगों का कहना है कि हवा से ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है। हम जानते हैं कि हवा में तकरीबन 78प्रति. नाइट्रोजन, 21प्रति. ऑक्सीजन और 1प्रति. नियॉन आर्गन जैसे गैस होती है। भारत में ऑक्सीजन उत्पादन की 10 से 12 बड़ी कंपनियां हैं और 500 के करीब छोटे-मोटे उद्यम हैं। ऑक्सीजन उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी गुजरात में है। पिछले साल कोरोना के आने के पहले भारत में प्रतिदिन 750 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन होता था। लेकिन हालिया स्थिति बहुत अधिक खतरनाक हो चुकी है। आज प्रतिदिन 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा हैं, जिसमें से 6,600 मीट्रिक टन राज्यों को चिकित्सा उद्देश्यों के लिए आवंटित किया जा रहा है। इसके अलावा उद्योगों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को प्रतिबंधित किया गया है ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन चिकित्सकीय उपयोग के लिए उपलब्ध हो सके। इसके बाद भी जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल सरकार ने अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस यानी ऑक्सीजन टैंकर लेकर ट्रेनें वहां पहुँच रही हैं जहां इसकी सबसे यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना मिलिट्री स्टेशनों से ऑक्सीजन भी एयरलिफ्ट कर रही है। सरकार 50 हज़ार टन लिक्विड ऑक्सीजन के आयात की भी योजना बना रही है।

कर दिए गए हैं। साथ ही शादी-विवाह सहित ऐसे कई अवसरों पर सीमित व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। जैसे शादी विवाह में 20 से अधिक लोग इकट्ठा नही होंगे, अंतिम यात्रा में 20-30 लोगों से यादा संख्या नही होनी चाहिए आदि आदि। सरकार व स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि कोरोना का संक्रमण तेज़ी से न फैले। यदि अधिक लोग एक साथ

Scanned with CamScanner

कोविड संक्रमण के नाम पर किसानों से लूट की छूट

कोविड-19 महामारी और इसके चलते लॉकडाउन के तहत मध्यप्रदेश की 269 मण्डियां लगभग बंद हैं। ऐसे में अपने को किसानों के हितचिंतक बताने वाली मध्यप्रदेश सरकार ने रबी फसलों की खरीदी के लिए सौदा पत्रक प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के अंतर्गत किसान मण्डियों का दौरा किए बगैर व्यापारियों को बुलाकर अपने दरवाजे उपज बेच सकते हैं। 24 अप्रैल से यह प्रणाली लागू कर दी गई है। हालांकि यह प्रणाली अगस्त 2019 से मध्यप्रदेश में लागू है, किन्तु इसका उपयोग अभी लॉकडाउन में प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। इसके लिए व्यापारियों के फोन नम्बर पोर्टल पर दे दिये गये हैं। जिससे किसान अपनी उपज बेचने के लिए सीधे व्यापारियों से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही व्यापारियों को भी किसानों से कितनी मात्रा में उपज खरीदी की गई तथा उसका भुगतान की प्रक्रिया कैसे और कितनी की गई है, इसका उल्लेख पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। जिससे सरकार के पास लेन-देन का पूरा आंकड़ा मौजूद रहे। यह प्रणाली मण्डी परिसर के बाहर व्यापारी और किसानों के बीच व्यापार प्रतिबद्धता का एक कानूनी दस्तावेज कहा जा सकता है। लेकिन किसानों का दर्द यह है, कि इस सौदा पत्रक प्रणाली के तहत खरीदी करने वाले एक भी व्यापारी किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य देने को राजी नहीं हैं। उनके पास इस समय समर्थन मूल्य से कम पर गेहूं बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। क्योंकि सहकारी समितियां अक्सर कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी के नाम पर बंद कर दी जाती हैं और लॉकडाउन के कारण शहरों की मण्डिया बंद है। किसानों को यह चिंता भी सता रही है, कि 30 अप्रैल के बाद उनके द्वारा लिये गये कर्ज पर उन्हें 12 से 14 फीसदी तक बैंक को ब्याज अदा करना होगा। वरना वे डिफाल्टर कहलायेंगे और उन्हें अगली फसल के लिए कर्ज भी नहीं मिलेगा। उधर व्यापारियों का कहना है, कि उनके पास समर्थन मूल्य देने के लिए पैसे नहीं हैं। इसी तरह औने-पौने दामों पर इंदौर जिले में व्यापारियों ने किसानों से एक लाख क्विंटल गेहूं की खरीदी कर ली है। वहीं मुरैना जिले पोरसा विकासखण्ड के ग्राम गिदौली के किसान शिवनाथ ने 50 क्विंटल गेहूं 1750 प्रति क्विंटल की दर से बेचकर व्यापारी से 87,500 नगद भुगतान प्राप्त कर लिये। इसी गांव के दिनेश ने 30 क्विंटल सरसों 3835 प्रति क्विंटल की भाव से बेची। इन दोनों फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य से कम पर की गई है। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1950 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि सरसों का 4650 रुपये निर्धारित किया है। यानी सब कुछ सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। छिंदवाड़ा जिले सहजपुरी गांव के किसान गुलाब सिंह पवार बताते हैं, कि उनके यहां सहकारी समिति में एक कर्मचारी के संमित होने से सेंटर को बंद कर दिया गया है और व्यापारी गेहूं के लिए 1200 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक देने को तैयार नहीं है। किसानों के पास पैसे नहीं है, इसलिए वे इस दाम पर गेहूं बेचने के लिए मजबूर हैं। इस तरह किसानों को सरकार की निगरानी में लूटा जा रहा है। चूंकि मध्यप्रदेश के 110 लाख हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन होता है और कभी-कभी तो यहां पंजाब से भी अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। सरकार के पास इतना सारा गेहूं प्रोक्योरमेंट की क्षमता नहीं है, इसलिए वह हमेशा ना-नुकुर करती है। आम तौर पर 30 अप्रैल के बाद सरकार के बहाने शुरू हो जाते हैं। कभी बारदाना न होने या कर्मचारियों की कमी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी का बहाना मिल गया है।

इकट्ठा होते हैं, तो इससे लोगों के संक्रमित होने का खतरा पूरा है और इसके बाद इस महामारी का विस्तार एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी और तेज़ी से होगा। इसलिए इन नियमों का पालन न करने वालों पर सरकार व प्रशासन सख्ती भी बरत रही है।

कोरोना की स्थिति बताते रो पड़े विधायक

मध्यप्रदेश में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला इंदौर की वर्तमान स्थिति को लेकर प्रेस कांफ्रेंस करते करते भावुक हो उठे। प्रेस कांफ्रेंस करते वक्त कांग्रेस विधायक के आंसू निकल आए। दरअसल इंदौर से कांग्रेस विधायक कोरोना को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे। इस बीच इंदौर शहर के बिगड़ते हालात और स्थानीय प्रशासन व सरकार से साथ ना मिलने की बात कहते हुए वे भावुक हो गए। प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है और मैं हर दिन अस्पतालों में लोगों की सेवा के लिए जा रहा हूं, लेकिन शहर के मंत्री और सांसद नदारद हैं। मैं सभी से विनती करता हूं कि कांग्रेस और भाजपा से ऊपर उठकर बीमार को दूर भगाने के लिए सभी नेता आगे आएं।

देश में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 42 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 70 हजार मौतें हुई हैं। केरल में 14 लाख से ज्यादा तो कर्नाटक में भी 13 लाख से ज्यादा केस हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 10 लाख से यादा केस हैं। पश्चिम बंगाल में सात लाख से यादा मामले हैं।

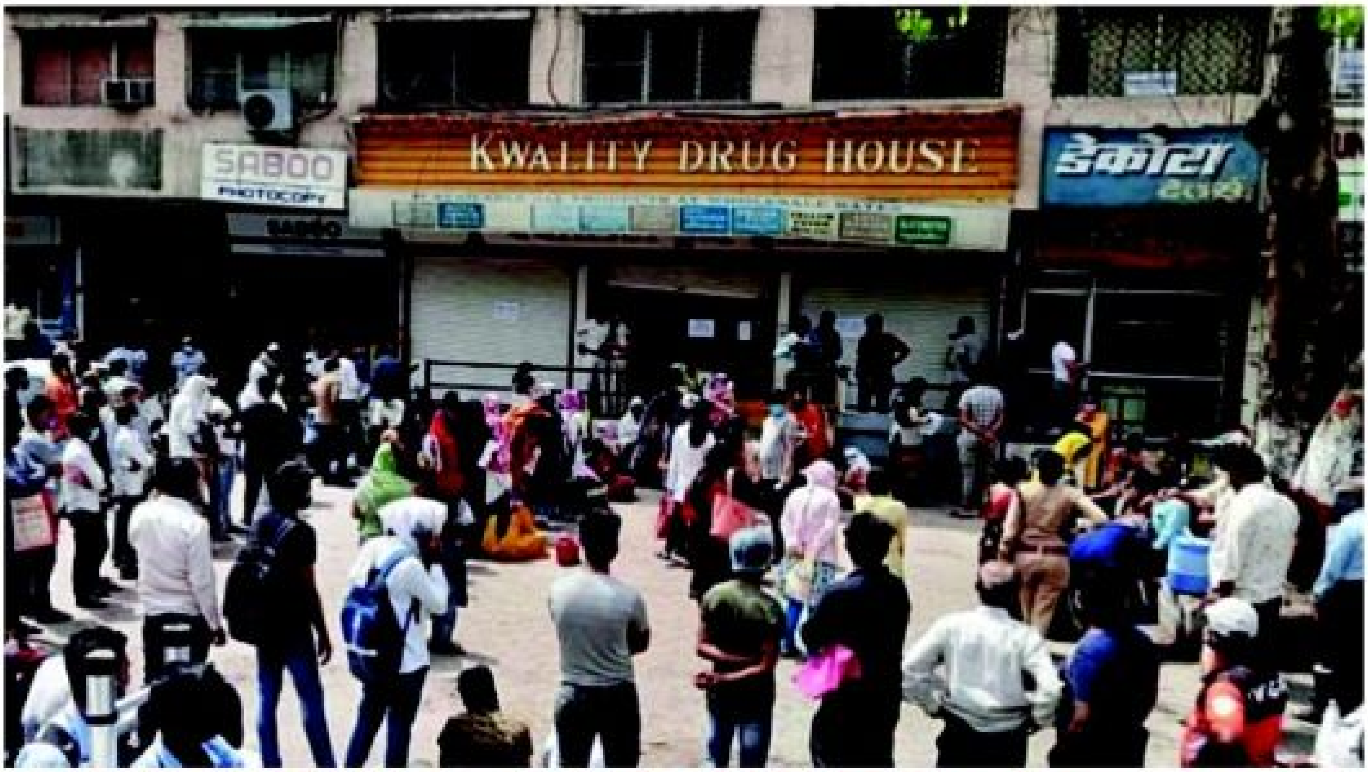

मेडिकल दुकान पर महत्वपूर्ण दवाईयां मिलने के इंतजार में लोग

Scanned with CamScanner

कोविड की जाँच के इंतजार में आमजन

छत्तीसगढ़ में छह लाख तो मध्यप्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, बिहार और राजस्थान में चार लाख से ज्यादा केस अब तक मिले हैं। असम और पंजाब में तीन लाख से ज्यादा मामले हैं। जम्मू कश्मीर, झारखंड और उत्तराखंड में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस हैं।

क्या क्रिकेट मैच बना करोना का कारण?

इस बीच मध्य मार्च में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच दो अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों को देखने के लिए एक लाख 30 हजार दर्शकों को इजाज़त दे दी गई। इनमें से ज्यादातर बग़ैर मास्क पहने आए थे और फिर इसके एक महीने के अंदर मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। भारत एक बार फिर कोरोना संक्रमण की गिरफ़्त में आ गया। कोरोना संक्रमण की यह दूसरी लहर बहुत ज्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है और इसने भारत के शहरों को बुरी तरह जकड़ लिया है। इस वजह से कई जगहों पर नए सिरे से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। कोरोना की इस दूसरी लहर में मध्य अप्रैल तक हर दिन संक्रमण के लगभग एक लाख मामले आने लगे।

देश में कुल संमित मरीज़ों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 73 लाख से उपर हो गयी है। जिनमें से दो लाख के लगभग लोगों की मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट घटकर 82.62 फ़ीसदी हो गया है, यानी देश में कुल पीड़ित मरीज़ों में से अब तक 1 करोड़ 43 लाख 4 हज़ार 382 मरीज़ों को ठीक किया जा चुका है। इसी के साथ देश मे अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 16.25 फ़ीसदी यानी 28 लाख 13 हज़ार 658 हो गयी है।

एमपी मे कोरोना से मौतों की तादाद सरकारी आंकड़ो से दोगुनी, श्मशानो के रिकॉर्ड मे सामने आई असलियत

मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से मौतों के आंकड़ों को लेकर सरकार के दावे झूठे साबित हो रहे, सरकारी दस्तावेज से श्मशानों और कब्रिस्तानों में दर्ज संख्या अलग है।

Scanned with CamScanner

कोरोना वायरस से मौत के आंकड़ों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार के दावे लगातार झूठे साबित हो रहे हैं। सरकार कहती है उसे आंकड़े छिपाकर कुछ नहीं मिलेगा लेकिन श्मशान, कब्रिस्तान में मौत के दर्ज आंकड़े कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है। पिछले माह मध्यप्रदेश में कोरोना से 5424 मौत के आंकड़े सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं जबकि अकेले अप्रैल 2021 में इससे दोगुना मौतें मध्यप्रदेश के शमशानों और कब्रिस्तानों के रिकॉर्ड में हैं। भोपाल के सबसे बड़े भदभदा श्मशान के दफ्तर में जब कर्मचारी पन्ने पलटने लगे तो कई महीने मार्च के आंकड़े दिखाने में खप गए। 20-25 पन्नों में अप्रैल के आंकड़े सरकार शायद नहीं देखती, इन कर्मचारियों ने बाकायदा कोरोना की मौतों को लाल स्याही से दर्ज किया है, कारण भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी। ममतेश शर्मा सचिव हैं भदभदा विश्राम घाट के, वो बताते हैं कि मार्च में 307 मृतक देह आई, 152 सामान्य, 155 कोरोना लेकिन अप्रैल

बेकाबू हालात के बीच कोविड की जाँच और वैक्सीनेशन में हो रही देरी

में विस्फोटक स्थिति आई। 2052 मृतक भदभदा में आए, 398 सामान्य, 1652 कोरोना से संमित। उन्होंने बताया, यहां परिजन फॉर्म भरते हैं, पूरा रिकॉर्ड रहता है शासन के विभाग हैं पुलिस, सीआईडी, प्रतिदिन आंकड़ा लेकर जाते हैं। यही हाल शहर के पहले कोरोना के लिये निर्धारित झदा कब्रिस्तान का है, लगातार अप्रैल में शव आते रहे। कमेटी का कहना है ऐसा खौफनाक मंज़र उन्होंने कभी नहीं देखा। झदा बिस्तान कमेटी के अध्यक्ष रेहान गोल्डन ने बताया, अप्रैल में भयानक स्थिति थी, 30 साल से कब्रिस्तान को देख रहा हूं। अप्रैल का ऐसा महीना, 388 शव आए। कभी ऐसा नहीं आया, रोज 4-5 शव आते थे। इस बार 15-18, 32 शव तक आए। सरकार 100 में 100 फीसद आंकड़े छिपा रही है, कुछ नर्सिंग होम के आंकड़े हैं जो सीधे घर को शव दे रहे हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है उसको आंकड़े छिपाकर अवॉर्ड नहीं मिलने वाला। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा चाहे डेथ का मामला हो या डेथ ऑडिट का ना इसको छिपाने की मंशा है ना जरूरत है, सरकार कोई आंकड़ा छिपा नहीं रही है। लेकिन सरकारी दावों से इतर अकेले भोपाल में कब्रिस्तान और श्मशान के आंकड़े जोड़ें तो कोरोना के 3811 शवों का अंतिम संस्कार हुआ जिसमें भोपाल जिले से 2557 शव थे। लेकिन सरकारी आंकड़ों के

वैक्सीनेशन के लिए इंतजार करते लोग

Scanned with CamScanner

लॉकडाउन तो लग जाता है लेकिन उन लोगों का क्या जो हर दिन कमाते हैं और हर दिन खाते हैं

मुताबिक पूरे अप्रैल में कोरोना से भोपाल में सिर्फ 104 मौत हुई। पूरे कोरोना काल में पूरे राय में मौत का सरकारी आंकड़ा अबतक 6420 है। जबकि भोपाल में 795।

नियम बनाने वाले खुद उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं

दरअसल एक तरफ जहां सरकार व प्रशासन द्वारा आम जनता से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने को कहा जा रहा है और आमजन पर सख्ती दिखाई जा रही है, वहीं नियमों को बनाने वाले और उनके पालन करने की दुहाई देने वाले खुद उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब जब पिछले महीने से कोरोना साल 2021 में अब तक अपने चरम पर है, इसी बीच बंगाल और असम जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव और उत्तरप्रदेश जैसे राज्य, जहां कोरोना महामारी के चलते हालात खराब होते जा रहें थे, वहां पंचायत चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों के दौरान बड़ी-बड़ी रैलियां, जनसंपर्क, रोड शो आदि आयोजित किए जा रहे थे। जिनमें भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी सब पार्टियां शामिल हो रही थी। हालांकि, बढ़ते मामलों को देखकर कांग्रेस ने अपनी सारी जनसभाओं को रद्द करने का फैसला लिया

Scanned with CamScanner

लॉकडाउन के ऐलान के बाद अफरा-तफरी में लोग

था। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद इन आयोजनों का एक बड़ा हिस्सा थे, जो बंगाल में सत्ता पाने की लालसा में देश की जनता के साथ दोहरी नीति अपना रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल की जनता के लिए चिंतित होने की बजाय अपनी कुर्सी को ज्यादा तवज्जो दे रही थी। बंगाल में भले ही राहुल गांधी ने अपनी जनसभाएं रद्द कर दी। वहीं अपने चुनावी प्रचार के दौरान मंचों से ये सारे राजनेता कोरोना महामारी की भयावह स्थिति और लोगों के दयनीय हालात को भूलकर पता नहीं जनता के किस हित, सरोकार और विकास की बात करते नज़र आते? चुनावी प्रचार खत्म होते ही खुद देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री आम जनता के समक्ष कोरोना नियमों का पालन करने और मौजूदा हालात पर चिंता ज़ाहिर करते हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां कोरोना को लेकर सरकार पर हमला बोलने लगती हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं और सरकार खुद कटघरे में खड़ी दिखाई पड़ती है।

सरकारों पर उठने वाले कुछ सवाल

क्या सरकारें और राजनैतिक पार्टियों को वास्तव में आम जनता की चिंता है? क्या नियम बनाने वाली सरकार खुद उन नियमों का पालन कर रही है? क्या कोरोना संबंधित नियम केवल

आम जनता के लिए बनाए गए हैं? क्या सरकार अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिए आमजन को खतरे में डाल रही है? क्या रैलियों और रोड शो में हज़ारों लाखों की संख्या में इकट्ठा होने वाली भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं है? क्या इन आयोजनों से कोरोना संक्रमण का विस्तार नहीं हो रहा है? क्या केवल स्कूल-कॉलेजों और छोटे दुकानदारों से ही कोरोना फैल रहा है? क्या मास्क केवल आम जनता के लिए ही ज़रूरी है? यदि नहीं तो बंगाल और आसाम में चुनावी प्रचार के दौरान कितने नेताओं और लोगों ने मास्क पहन रखा था? क्या वहां कोरोना नियमों का पालन हुआ? ऐसे कई सवाल हैं जो आम जनता के मन में उठ रहे हैं

केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों ने कोरोना के साथ में बड़े-बड़े आयोजन करने की अनुमति क्यों दी? जैसे- क्रिकेट का आयोजन, कुंभ का आयोजन, चुनाव की अनुमति देने की क्या जरूरत थी।

और उठाना भी जायज़ है, क्योंकि इन नियमों और पाबंदियों की वजह से आम जनता को कई बार चालान भी भरना पड़ रहा है। लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। सामाजिक दूरी के नाम पर शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुकी है। लोगों का भविष्य अधर में है। लोग रोजी-रोटी को मोहताज हैं। ऐसी तमाम समस्याएं और अव्यवस्थाएं हैं, जिनका सामना केवल और केवल आम जनता को करनी पड़ रहा है।

राजा पालन करता है, तभी प्रजा प्रभावित होती है

हालांकि, इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन न किया जाए। निश्चित रूप से इस भयावह स्थिति में जनता को मास्क सहित सभी नियमों का पालन करना चाहिए। मगर खुद नियम बनाने वालों द्वारा उन नियमों की

ये है अहमदाबाद का नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ भारत इंग्लैंड का मुकाबला हुआ था। इस मैच में हजारों की भीड़ इकठ्ठा हुई थी। कोरोना फैलाने में ये कारण हो सकते है।

Scanned with CamScanner

पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हजारों की संख्या में लोग रैलियों में शामिल हुए। जबकि उस समय कोरोना का कहर चरम पर था। ऐसे में इस तरह की लापरवाहिंया सोचने पर मजबूर करती है। आज बंगाल की स्थिति बेहद खराब है।

धजियां उड़ाई जाय और आम जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए तो जनता निश्चित रूप से खुद को बेवकूफ ही समझेगी और उनका आोशित होना भी जायज़ है। शुरुआत से बताया जाता रहा है कि किसी राज्य देश की प्रजा में बदलाव के लिए सबसे पहले राजा स्वयं उन नियमों या बदलाव का पालन करता है। इससे उसकी प्रजा ज्यादा प्रभावित होती है और उसका अनुसरण करती है। ऐसे में आज जब देश का राजा प्रजा की चिंता करने की बजाय, खुद के बनाए नियमों की धजियां उड़ा रहा हो तो प्रजा से उसके पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सालभर बाद भी पार्टियां बस सरकार बनाने और बचाने में परेशान हैं। मौजूदा स्थिति यह सोचने को मजबूर करती है कि इस लोकतांत्रिक देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार किस हालत में हैं? सही मायने में ये सब ठप पड़े हुए हैं। यदि महामारी के

ये कैसी मानवीयता है। गंगा जैसी पवित्र नदी में शवों को बहाया जा रहा है। यह किसने किया, क्यों किया, चिंतनीय विषय है

कारण जनता के हित के लिए स्कूल, कॉलेज, संस्थान, दुकान, यात्रा, सामाजिक उत्सव, आयोजन, शादी-विवाह आदि स्थगित हो सकते हैं तो चुनाव और बड़ी-बड़ी रैलियां क्यों नहीं? क्या चुनाव आम जनता के जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा ज़रूरी है? हालांकि, कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या, रिकवर करने वालों से बहुत कम है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बताया कि कोरोना के कारण मृत्यु दर मात्र 1.87प्रति. है लेकिन देखा जाए तो इनमें से अधिकतर मृत्यु पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के न होने के कारण हुई हैं। साल 2020 की शुरुआत में जब कोरोना की लहर शुरू हुई थी तो सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए गये। ढेर सारे फंड पास किए गए और इससे मुक्ति के दावे किए गए। बेहतर व्यवस्था का आश्वासन दिया गया। कुछ महीनों बाद कोरोना से जंग में जीत का डंका पीटा गया और एक बार पुनः सब सामान्य होने का दावा किया गया। मगर वास्तविकता यह है कि आज लगभग एक साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं, जहां मार्च 2020 में थे। आज भी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। लोग अस्पतालों में बेड, वैक्सीन, ऑक्सीजन और सुविधाओं को लेकर परेशान और बेहाल हैं। कोरोना पर नियंत्रण नहीं है और तमाम दावे और सवाल उठाने वाली पार्टियां आज बस अपनी सरकार बचाने और बनाने में परेशान हैं।

टीकाकरण

सरकार लगातार टीकाकरण के संबंध में ऐसे एलान करना जारी रखे हुए है, जो वास्तव में जो हासिल हुआ है, उससे बहुत बढ़-चढ़कर दावे करते हैं। पहला दावा तो यही

हरिद्वार कुंभ का आयोजन भी ऐसे समय हुआ, जब देश भर में कोरोना का कहरचल रहा था। कुंभ में लाखों लोग शामिल हुए थे, हालांकि बाद में कुंभ के आयोजन को निरस्त कर दिया गया था। इस कुंभ में हर प्रदेश से लोग शामिल हुए और संक्रमित हुए, जिनमें ज्यादातर मर भी चुके है।

है कि हमने 12.7 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया है। यह सच नहीं है। 12.7 करोड़ टीके की खुराकें जरूर लगायी जा चुकी हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या 2 करोड़ भी नहीं है, जिन्हें दोनों खुराकें लगायी जा चुकी हैं, जो कि जरूरी हैं। अप्रैल की शुरूआत से ही महाराष्ट्र, दिल्ली तथा पंजाब जैसे राज्यों ने टीके की आपूर्तियां बहुत कम रह जाने की शिकायत करना शुरू कर दिया था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उनकी शिकायतों को यह कहकर खारिज कर दिया कि वे तो इस मामले में राजनीति कर रहे हैं ताकि कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने में अपनी विफलता पर पर्दा डाल सकें। राज्यों को भेजे अपने पत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा था कि जब तक टीकों की आपूर्ति सीमित बनी हुई है, इसके सिवा दूसरा विकल्प ही नहीं है कि टीका पाने के लिए प्राथमिकता म तय किया जाए। यह दुनिया भर में भी स्वीकृत तरीका है और सभी राज्य सरकारें इससे अच्छी तरह से परिचित हैं। लेकिन अगर एक पखवाड़े पहले यह नीति वाकई सही थी तो क्या मोदी सरकार बताएगी कि वह अब 18 साल से यादा के सभी लोगों के टीकाकरण का दरवाजा क्यों खोल रही है? नीति में इस बदलाव का कोई स्पष्टीकरण दिया ही नहीं गया है जबकि न सिर्फ टीकों की आपूर्ति अब भी सीमित ही बनी हुई है बल्कि दो-तीन हफ्ते पहले जिस स्तर पर थी उससे आधी ही रह गयी है। यही नहीं इसकी कोई योजना भी नहीं बतायी गयी है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों

मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से मौतों के आंकड़ों को लेकर सरकार के दावे झूठे साबित हो रहे

Scanned with CamScanner

के टीकाकरण के विस्तारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारा देश टीके के उत्पादन तथा वितरण के पैमाने को कैसे बढ़ाने जा रहा है? उल्टे केंद्र सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों आदि फ्रंटलाइन वर्करों तथा 45 साल से अधिक आयु के लोगों को छोड़कर बाकी सब के लिए टीके लाने या वितरित करने की पूरी की पूरी जिम्मेदारी से ही हाथ खींच लिए हैं। वह देश के टीका उत्पादन के 50 फीसद में से ही इस जरूरत की आपूर्ति करेगी। शेष 50 फीसद उत्पादन, राज्य सरकारों और खुले बाजार के लिए रहेगा। राज्य सरकारों पर सीधे अपनी जरूरत के टीके खरीदने की जिम्मेदारी होगी, जबकि ऐसा करने का कोई तंत्र उनके पास नहीं होगा। केंद्र सरकार ने टीकों की कीमतों का नियंत्रण भी खत्म कर दिया है और टीका निर्माताओं को अब खुले बाजार में अपने टीके बेचने का मौका दिया जाएगा।

वैक्सीन का प्रभाव कब

अगर वैक्सीनेशन से बनने वाली इम्यूनिटी की बात करें कि छह करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीन को कोरोना से लड़ाई में एक बड़ा हथियार बताया गया है, लेकिन, उसका प्रभाव अभी साफतौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि वैक्सीनेशन का प्रभाव दिखने में अभी काफी समय लगेगा। वैक्सीन तभी असर करती है जब उसके दोनों डोज़ लग जाते हैं। पहली डोज़ के लगभग एक महीने बाद दूसरी डोज़ लगती है और उसके 14 दिनों बाद इम्यूनिटी बननी शुरू होती है। ऐसे में अभी सवा सौ अरब की आबादी में से छह करोड़ को ही वैक्सीन लगी है। वो लोग और भी कम हैं जिन्हें दूसरी डोज़ लग चुकी है। इसलिए वैक्सीन का प्रभाव दिखने में अभी वक़्त लगेगा। भारत में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। पहले स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन दी गई। उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों वाले 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इसे खोला गया। अब 01 मई से 18 वर्ष से उपर वाले सभी लोगों को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं, डॉक्टर बताते हैं कि जब तक किसी भी जगह पर एक पर्याप्त आबादी को वैक्सीन के माध्यम से सुरक्षा नहीं मिल जाती तब तक उसे रोक पाना मुश्किल है। वैक्सीनेशन पर निर्भरता अभी लाभदायक नहीं है। वैक्सीन का फायदा तब होगा जब पर्याप्त संख्या में लोग वैक्सीनेट हो जाएं।

तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरा, अस्पतालों में बेड बढ़ाने की आवश्यकता

मध्यप्रदेश में इंदौर जिले के गाँव में एक महीने में 1764 और ग्वालियर में 42 के भीतर 1460 बच्चे संक्रमित हुए।

लॉकडाउन सबसे कारगर तरीका नहीं

आज भी कई लोग लॉकडाउन को कोई बेहतर विकल्प नहीं मानते। वह कहते हैं पिछले साल लॉकडाउन लगाने का उद्देश्य स्वास्थ्य तंत्र को कोविड-19 से लड़ने के लिए और लोगों को कोरोना वायरस के ख़तरे और बचाव के लिए मानसिक रूप से तैयार करना था। उस दौरान लोगों ने वायरस को समझा

Scanned with CamScanner

कारगर वैक्सीन का उपयोग करें भारत

सूत्रों के मुताबिक देश के ताकतवर लोगो को फाईजर की वैक्सीन लगी है

कोरोना की दूसरी लहर में जो तकलीफें भारत झेल रही हैं, वह ब्रिटेन और अमेरिका पहले ही झेल चुके थे। पर तेजी से टीकाकरण, आने वाली चुनौतियों को समझकर रणनीति तैयार कर उन्होंने संक्रमण से होन वाली मौतों पर लगभग रोग लगा दी। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) को भी इसका श्रेय है। अमेरिका, रूस जैसे देश ने कोरोना पर कंट्रोल कर लिया फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं? जो वैक्सीन अमेरिका, रूस में लगाई जा रही है वह वैक्सीन भारत में क्यों नहीं आ पा रही है। सूत्रों की माने तो देश के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली लोगों ने फाईजर की वैक्सीन लगवा ली, जबकि आम जनता के लिए यह अभी उपलब्ध नहीं हो सकी। इस कोरोना काल में इन ताकतवर लोगो को समझ नहीं आ रहा है कि देश में राजतत्र नहीं लोकतंत्र है और आने वाले चुनावों में निश्चित ही आम जनता वोट के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त करेगी। भारत भी अमेरिका से वही वैक्सीन खरीद सकती है। अमेरिका में अब लोगों को मास्क हटाने को कह दिया है। भारत को भी लोगों की जिंदगी के विषय में सोचना चाहिए। आखिर जो वैक्सीन ज्यादा कारगर है उसी वैक्सीन का उपयोग भारत को करना चाहिए। चाहे इसके लिए कितनी भी राशि क्यों न खर्च करनी पड़े। भारत को चाहिए कि वह विकसित देशों की वैक्सीन अपने देश में लगवाए।

और मास्क पहनने, हाथ धोने व सोशल डिस्टेंसिंग रखने की आदत डाली। अब वो उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। अब अगर एक साल में स्वास्थ्य तंत्र तैयार नहीं किया और लोग जागरुक नहीं हुए तो उन्हें कुछ दिनों में तैयार नहीं किया जा सकता। एक दिन के लॉकडाउन भी नुकसान कर सकते हैं। जैसे अगर रविवार को लॉकडाउन लगाया गया तो जिन्हें रविवार को बाहर जाना था वो अब सोमवार को जाएंगे। ऐसे में सोमवार को भीड़ बढ़ेगी और संक्रमण की संभावना भी बढ़ेगी। इसलिए कोविड-19 से लड़ाई में इस वक्त सावधानी बरतने से ज्यादा कारगर

तरीका कोई नहीं है। वैक्सीन के अपने फायदे हैं लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को कभी नहीं भूलना है।

कोरोना की सामाजिक चुनौतियां

कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के वैश्विक प्रसार के साथ-साथ हर समाज की विसंगतियां भी सामने आ रही हैं, चाहे वह विकसित समाज हो या विकासशील समाज। कोरोना वायरस हमें ऐसी चीजें बता रहा है, जिन्हें हम आमतौर पर स्वीकार नहीं करना चाहते। यह हमें समृद्ध देशों में मौजूद असमानताओं को पहचानने के लिए भी बाध्य कर

Scanned with CamScanner

रहा है। जैसे अमेरिका में, जहां संक्रमण के 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और चार दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं, विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि लोग भीड़ में जाने से बचें, और यदि वे संदिग्ध मरीज के रूप में अलग-थलग रखे गए हैं, तो लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थ इकट्ठा कर लें, घर पर रहें तथा बीमार होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन उस सलाह के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या है कि बहुत से निम्न आय वाले लोग इसका पालन नहीं कर सकते। कम आय वाली नौकरियां (जैसे रसोइया, नर्स, किराने की दुकान के कर्मचारी, आया) दूर रहकर नहीं की जा सकतीं और यादातर कम आय वाली नौकरियों में बीमारी के दिनों का भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे यादातर लोगों के पास या तो बीमा नहीं होता या होता भी है, तो कम राशि का होता है। ऐसे अनेक लोगों के लिए खाद्य पदार्थ इकट्ठा करके रखना वित्तीय बाधा के चलते असंभव हो सकता है। अनेक लोगों को घर से काम करने, भीड़भाड़ से बचने, कोरोना से मिलते-जुलते लक्षणों की अनदेखी न करने, बार-बार साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए कहा गया है। ऐसे कितने लोग हैं, जो घर से काम कर सकते हैं और इन सलाहों का पालन कर सकते हैं। अपने यहां असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की बहुत बड़ी आबादी है। लाखों ऐसे दैनिक वेतनभोगी हैं, जिन्हें बीमारी के दौरान छुट्टी का भुगतान नहीं किया जाता। अगर कोरोना वायरस का संक्रमण स्थानीय स्तर पर होता है, तो आबादी का गरीब तबका, मसलन, ड्राइवर, घरेलू नौकरानियां, प्रवासी मजदूर और अन्य लोग निश्चित रूप से भारी नुकसान में रहेंगे, क्योंकि वे उतने शिक्षित नहीं हैं कि नए कोरोना वायरस के बारे में पर्याप्त रूप से अवगत हों। फिर वायरस की जांच सबके लिए नहीं है, ऐसे में, उनकी जांच नहीं की जाएगी और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं तक उनकी पहुंच तो कठिन और असंभव है। सरकारी अस्पतालों में न तो पर्याप्त आईसीयू हैं और न ही वेंटिलेटर, इसलिए गरीब लोग इससे यादा प्रभावित हो सकते हैं। अभी तक वायरस के सामुदायिक स्तर पर प्रसार की पुष्टि नहीं हुई है। यानी सामान्य आबादी में वायरस की पहचान नहीं हुई है। जब सामुदायिक स्तर पर संक्रमण होता है, तो बीमारी इस तरह फैलती है कि संक्रमण के स्रोत का पता नहीं होता। कार्यस्थल पर या खरीदारी करते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैल सकता है और वैसे लोगों से भी संक्रमण फैलता है, जिन्हें संभवतः पता नहीं होता कि वे संक्रमित हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत में अब तक बहुत से लोगों का परीक्षण ही नहीं किया गया है और इसके साथ शिक्षा, स्वस्थ आचरण के प्रति जागरूकता की कमी, गरीबी और देश के कई हिस्सों में कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली आने वाले दिनों में चुनौती होगी। बार-बार साबुन से हाथ धोना एक अच्छा उपाय हो सकता है, जिसे कोई व्यक्ति मानक स्वास्थ्य सावधानी के साथ कर सकता है। इस मामले में भी भारत की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। भले ही भारत के लगभग सभी घरों में (हालिया सर्वे के अनुसार 97 फीसदी

Scanned with CamScanner

सरकार की नाकामी, फुटपाथ पर आक्सीजन

घरों में) वाश बेसिन है, लेकिन केवल धनी और शहरी क्षेत्रों के ज्यादा शिक्षित परिवार ही हाथ धोने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं। अमीर और गरीब परिवारों के बीच भारी असमानता है। दस गरीब परिवारों में से केवल दो में ही हाथ धोने के लिए साबुन का प्रयोग होता है, जबकि दस अमीर परिवारों में से नौ में साबुन का इस्तेमाल होता है। विषमताओं को गहरा करने में जाति और वर्ग बराबर भूमिका निभाते हैं। भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के परिवारों में हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल सबसे कम होता है। संकट एक

विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल और असम में कोरोना का हाल

बंगाल – टेस्ट नहीं बढ़ाये, तब भी अस्पताल फुल

असम – तीन दिन में 2012 मौतें गांव में बुरा हाल

अवसर भी बन सकता है। वर्ष 1994 में सूरत में प्लेग का प्रसार किस तरह स्थानीय प्रशासन में सुधार की वजह बना था, इसे लोग जानते हैं।

निश्चित तौर पर कोरोना के कारण हालात बहुत खराब हुए हैं। अब लोगों की उम्मीदें बंधी है कि सरकार स्वयं लोगों की मदद के लिए आगे आए। आजीविका से जुड़ी बातों पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार के साथ-साथ विपक्ष को भी आगे आकर सरकार के साथ चलना होगा। क्योंकि यह बहुत चिंताजनक समय चल रहा है। जिसमें सहयोग की महती

Scanned with CamScanner

अंतिम संस्कार के लिए भी लंबी लाईन

आवश्यकता है। किसान,गरीब, मजदूर, युवा सभी को सहयोग की जरूरत महसूस हो रही है। जहां तक मध्यप्रदेश की बात की जाए तो इतिहास में अभी तक इतनी बड़ी त्रासदी प्रदेश में नही आयी। इस संकट में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाऐं पूरी तरह विफल रही है। महानगरों से लेकर गांवों-गांवों तक स्वास्थ्य सेवाऐं ठप्प हो गई। लोगों को इलाज तक नसीब नही हो रहा है। मुख्यमंत्री को इस समय में बहुत संवेदनशील होने का समय है।

इस समय कम से कम वह स्वास्थ्य के मामले में तो सुविधाए मुहैया कराए। जो भी समस्या आयी या आ रही है उनसे सिर्फ सरकार को प्रयासों से ही हल किया जा सकता है। मेरा यही कहना है कि शिवराज जी इस समय स्वास्थ्य की सेवाऐं बेहतर करने का प्रथम प्रयास करें। लॉकडाउन जैसी स्थिति में सरकार को करना चाहिए कि वह नगरों में नगर निगम के माध्यम से लोगों के घर तक जरूरी सामान पहुंचाए। आवश्यकता पड़ने पर सरकार भी लोगों की आर्थिक मदद करें और सबसे प्रमुख ईलाज के दौरान प्रायवेट अस्पतालों में जो लूट खसोट मची है उस पर अंकुश लगाए। क्योंकि वर्तमान समय में हर एक इंसान बहुत बुरी तरह से बिखर गया है, टूट गया है। पूरे देश में लॉकडाउन लगना चाहिए, साथ ही लोगों की जिंदगी भी चलती रहे, जिसके लिए व्यवस्थायें, घर-घर जाकर वेक्सीनेशन की सुचारू व्यवस्था सहित अन्य इंतजाम भी पुख्ता होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

कोरोना संक्रमण को रोकने में असफल साबित हुई भूपेश सरकार

कोरोना संक्रमण में राज्य को नंबर-1 बनाना चाहते हैं भूपेश बघेल

समता पाठक

देश में कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र के बाद जिस राज्य में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, वो है छत्तीसगढ़। यहां हर रोज आने वाले नए मामले रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। दोनों ही मामलों में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। देशभर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेजी से चलाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना संक्रमण के मामले दिन व दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ भी खुद को बचा नहीं सका है। राज्य में हालात ये हैं कि आए दिन लोगों की मौतें होने का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। प्रदेश में हर दिन हजारों लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हो रही है। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर साढ़े 04 लाख से अधिक हो गई है। 10 अप्रैल को राज्य में 14,098 नए मामले सामने आए थे, जो कि एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा थे। वहीं 123 लोगों की मौत हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। राज्य में वायरस से अब तक 6 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई है। 1 अप्रैल को राज्य में 4600 से ज्यादा नए केस सामने आए थे, जो कि अब 10 दिन में ही 14 हजार से ज्यादा हो गए। लगातार कोरोना मरीजों

Scanned with CamScanner

की हो रही मौतों से बेखबर राज्य सरकार अपनी दुनिया में मस्त है। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल को न राज्य की जनता की और न ही उनके स्वास्थ्य की चिंता है। तभी वो कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में उचित कदम नहीं उठा रहे हैं। यह बात भी सच है कि प्रदेश में कोरोना के हालात सबसे ज्यादा उस समय से बिगड़े हैं जब रायपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था। इस टूर्नामेंट में लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। कोरोना का यह पीक समय था। यदि इस समय ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सतर्क हो जाते और इस ओर ध्यान दे देते तो शायद आज यह हालात नहीं होते। इस टूर्नामेंट ने प्रदेशवासियों को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। निश्चित तौर पर इसके जिम्मेदार भूपेश बघेल हैं। वहीं वह टूर्नामेंट में मैच देखने के दौरान पूरे समय बिना मास्क के रहे। सीएम खुद बिना मास्क के रहे तो आमजन भी बेफिक्र रहे। दूसरी तरफ सीएम लोगों से मास्क पहनने की अपील भी कर रहे हैं लेकिन खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं भूपेश सरकार ने अब तक प्रदेश में रेमडेसिवीर इंजेक्शन की व्यवस्था तक नहीं की है। जहां हर

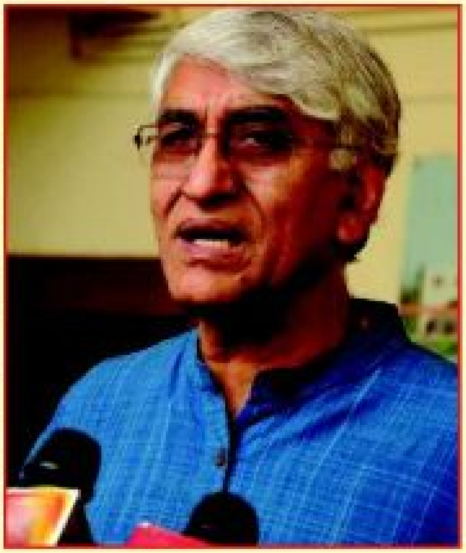

ये हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जो कोरोना महामारी के दौर में हालात को सुधारने का प्रयास कर रहें हैं। प्रारंभ से ही कोरोना को कंन्ट्रोल करने की जुगत करते रहे हैं लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इनकी एक न चलने दी। कोरोना के दौर में ही मुख्यमंत्री ने राज्य में बड़े-बड़े आयोजन कर दिए जिससे छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नम्बर पर आ गया। अब हालात इतने बेकाबू हो गए है कि सरकार के बस में ही नहीं रही है। वहीं सीएम भी हमेशा से इनकी अनदेखी करते रहे हैं। यहां तक इन्हें मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता है।

Scanned with CamScanner

दिन राज्य को 10 हजार डोज की आवश्यकता बताई जा रही है वहीं, राज्य में इंजेक्शन सप्लाई की व्यवस्था पूरी तरह ठप है। बावजूद उसके पिछले दिनों भूपेश सरकार ने प्रदेश में क्रिकेट टूर्नामेंट, राज्यकुंभ जैसे बड़े आयोजन कर लाखों लोगों की भीड़ होने दी और खुद की आंख पर पट्टी बांध रखी। बताया जा रहा है कि सरकार का पूरा फोकस इस समय धन बटोरने में है।

फरवरी माह में एवं मार्च के पहले सप्ताह में 27.29 प्रति सप्ताह मौत हुई थी। जनवरी के अंतिम सप्ताह में 43 लोगों की मौत हो गई। वहीं, दुर्ग जैसे शहर में शमशान घाट में अंतिम संस्कारों के लिए लाइन लगी पड़ी है और 200 से अधिक मृतक शरीर अंतिम संस्कार की प्रतिक्षा सूची में हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य सरकार संक्रमण को रोकने में बुरी तरह से असफल हुई है। भूपेश बघेल को चाहिए कि वो खुद उच्च स्तरीय सवर्दलीय कमेटी गठित करें, विपक्षी नेताओं से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। क्योंकि यह समय संकट का है। पूरा प्रदेश संकट में है। इसमें क्या पक्ष और क्या विपक्ष। सबको मिलकर इस संक्रमण को रोकना होगा। वहीं संक्रमण किसी एक पार्टी या सरकार से नहीं

कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, दवाएं नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है वहीं राज्य की सरकार बैठकर तमाशा देखने में मशमूल है। छत्तीसगढ़ देश में कोरोना प्रभावित राज्यों में दूसरे नंबर पर है। जिसके लिए सीएम भूपेश बघेल जिम्मेदार है।

Scanned with CamScanner

असम के साथ छत्तीसगढ़ भी हार बैठे हैं भूपेश बघेल

असम मे कांग्रेस की हार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की व्यक्तिगत हार रही, इस हार के साथ भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को भी हरा दिया। पूरे प्रदेश को अपने महा-भ्रष्टाचारी अवैध वसूली गैंग के भरोसे छोड़ कर चले गए। इस गैंग में एक आरोपी आईएएस अधिकारी, एक महापौर के छोटे भाई एवम एक पूर्व मुख्य सचिव है जिन्होंने भ्रष्टाचार के ऐसे-ऐसे नायाब फार्मूले निकाले जिसका कोई सानी नहीं है। इस समय प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का कोहराम इन्होने फैला दिया है उसकी चुभन आम छत्तीसगढ़िया महसूस कर रहा है। छत्तीसगढ़ मे भ्रष्टाचार का एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना दिया गया है। प्रदेश की ढाई करोड़ जनता को यह उम्मीद थी कि कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश मे विकास की गंगा बहेगी पर खोखले वादों तथा सत्ता पाने के लिए आम जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली इस भूपेश बघेल सरकार के लिए आने वाले दिन बहुत भारी पडने वाले हैं। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जनता के गाढ़े पसीने की कमाई के करोड़ो अरबों रुपए लुटाए जा रहे हैं तथा मुख्यमंत्री बघेल राष्ट्रीय हीरो बनने की चाहत में विज्ञापनों में पानी की तरह पैसा बहा कर आम जनता के मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहे हैं। नरवा, गरुवा घुरवा और बारी की हकीकत बेनकाब हो चुकी है। गोठान की सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर रसूखदार कांग्रेसियों तथा भू-माफियाओं का कब्जा हो चुका है। ढाई साल के अल्प काल में ही पूरे प्रदेश के सैकड़ों तालाब पाटकर बेच दिए गए हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार डी एम एफ फंड से किसी भी जिले में 25 फ़ीसदी से अधिक का काम नही हुआ है और भुगतान उठा लिया गया है। इस प्रकार राज्य के आर्थिक ढांचे को तबाह कर खजाने को खाली कर दिया। जिन किसानों की बात यह करते है उनको फसल का पुरा पैसा नहीं दिया गया। पैसा इतनी किश्तो मे दिया गया कि किसानों को उसका वास्तविक लाभ ही नहीं मिल पाया। जिस न्याय योजना का बखान मे करोडो रुपये देश भर के विज्ञापनों में फूंक दिए गए और जब उसकी पुरी किश्त नहीं दे पाए तो ठीकरा केंद्र पर फोड़ दिया। असम में कांग्रेस की वापसी की गारंटी देने वाले मुख्यमंत्री बघेल असम चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाते रहे। यहां तक कि चुनाव खत्म होने के बाद असम के कांग्रेसी एवम सहयोगी दल के विधायक उम्मीदवारों को शानदार रिसोर्ट में सरकारी खर्चे पर मेहमान नवाजी कराते रहे। उन उम्मीदवारों के चुनाव में पराजित होने के बाद, उन पर खर्च हुए लाखों रुपए भी डूब गए। कोई ढाई महीने असम में रहने वाले भूपेश बघेल ने अनेको बार अपने बड़बोलेपन से छत्तीसगढ़ का मान घटाया। इसका एक उदाहरण उनका दिये साक्षात्कार है जिसमे उन्होने हेमंतबिश्व शर्मा का मजाक उड़ाया और बाद मे हेमंतबिश्व शर्मा ने अपने साक्षात्कार मे कहा कि जब वे कांग्रेस मे थे तब उन्होंने भूपेश बघेल का नाम तक नहीं सुना था छत्तीसगढ़ से टी.एस.सिंहदेव का ही नाम सुना था।

रोका जा सकता है इसके लिए सभी दलों के नेताओं को एकजुटता दिखानी होगी। खासतौर से भूपेश बघेल को अपने सलाहकार सदस्यों की बातों को गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि संक्रमण के इस गति में ब्रेक लगाया जा सके। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से अभी तक संक्रमण को रोकने के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए। अगर भूपेश बघेल एंड कंपनी राज्य में शुरूआती दौर में ही संक्रमण को रोकने कोई कड़े कदम उठा लेती तो आज राज्य की जनता की हालत ऐसी नहीं होती। अस्पताल हो या फिर घर हर जगह संक्रमित लोग परेशान हैं और सरकार लोगों की परेशानी से पूरी तरह अंजान। अस्पतालों में न तो पर्याप्त इंतजाम हैं और न ही लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक करने का कोई प्लान। अगर सरकार ने इस कैजुअल एप्रोच

Scanned with CamScanner

के साथ संक्रमण रोकने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ राज्य देश के सबसे ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों की सूची में नंबर वन पर होगा।

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को अंधेरे में रख रहे मुख्यमंत्री- प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर स्वास्थ्य को मंत्री टीएस सिंहदेव काफी चिंतित हैं और हर पल इस महामारी से बचाव के कारणों पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री अपने स्तर पर कोरोना की स्थिति में सुधार के लिए प्रयासरत हैं वही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में भी वह प्रदेश के बाहर रहने में मस्त हैं। सब जानते हैं कि इस समय प्रदेश में कोरोना भयानक स्थिति में पहुंच चुका है। दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री अपने सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री को अंधेरे में रखने की कोशिश करते हैं। कोरोना की सही जानकारी तक मुहैया नहीं कराते।

मुख्यमंत्री अपने सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री को अंधेरे में रखने की कोशिश करते हैं। कोरोना की सही जानकारी तक मुहैया नहीं कराते। जिस कारण से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले कार्य बाधित हो रहे हैं। इस तरह की कार्यशैली तो निश्चित तौर पर प्रदेश के हित में नहीं हैं और कोरोना संक्रमणों की स्थिति और बिगड़ेगी।

जिस कारण से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले कार्य बाधित हो रहे हैं। इस तरह की कार्यशैली तो निश्चित तौर पर प्रदेश के हित में नहीं हैं और कोरोना संक्रमणों की स्थिति और बिगड़ेगी।

दुर्ग में हुई 38 मौतों का जिम्मेदार भूपेश बघेल?- देश में कोरोना की दूसरी लहर की शुरूआत होते ही इस संक्रमण ने कई राज्यों को अपने चपेट में लिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य इस वायरस से अछूते नहीं रह पाए हैं। वायरस के इस संक्रमण से जनता को बचाने के लिए निरंतर जहां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सरकार कई कड़े कदम उठा चुकी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। सत्ता में काबिज भूपेश बघेल की सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर कितनी चिंतित है इस बात अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कई हजार से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस है और भूपेश सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई हैं। राज्य की जनता दिन प्रतिदिन संक्रमित होती जा रही है और भूपेश बघेल और उनके राज्य के मंत्री सिर्फ लूट खसोट करने में जुटे हुए है। अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए के बजट को काला-पीला दिखाकर डकार लेने में माहिर भूपेश बघेल के लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है दुर्ग में कोविड के

Scanned with CamScanner

कारण एक ही दिन में हुई 38 लोगों की मौतें। आखिर इस दुःखद घटना का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों नहीं भूपेश सरकार कोरोना संक्रमण रोकने जरूरी कदम उठाती। एक तरफ जब संक्रमण से बचाव के लिए हर राज्य सरकार दुकान, हाट बाजार, सांस्कृतिक आयोजन, खेल गतिविधि आदि पर रोक लगा रही थी, तब भूपेश सरकार ने महज रूपयों के लालच में आकर राज्य में रोड सेफ्टी क्रिकेट चैंपियनशिप कराए जाने पर सहमति जताई थी। नतीजा स्टेडियम के अंदर लाखों लोगों की भीड़ और राज्य में कोविड से बचाने में सफल रहे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी छत्तीसगढ़ आकर कोविड संक्रमण के जाल में फंस गए। चैंपियनशिप समाप्त होने के कुछ दिन बाद ही उनकी कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। यही वजह है कि लगभग एक वर्ष से भी अधिक समय से खुद को कोविड से बचाने में सफल रहे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी छत्तीसगढ़ आकर कोविड संक्रमण के जाल में फंस गए। चैंपियनशिप समाप्त होने के कुछ दिन बाद ही उनकी कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई।

राज्य सरकार संक्रमण को रोकने में बुरी तरह से असफल हुई है। भूपेश बघेल को चाहिए कि वो खुद उच्च स्तरीय सवर्दलीय कमेटी गठित करें, विपक्षी नेताओं से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। क्योंकि यह समय संकट का है। पूरा प्रदेश संकट में है। इसमें क्या पक्ष और क्या विपक्ष। सबको मिलकर इस संक्रमण को रोकना होगा। वहीं संक्रमण किसी एक पार्टी या सरकार से नहीं रोका जा सकता है

ऐसे समय में जब जनता संमण से जूझ रही थी तब भूपेश बघेल का लापरवाह रवैया कहीं न कहीं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को खुद का प्रतिस्पर्धी मानने वाले भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव की छवि को धूमिल करने के लिए अब तक कोविड रोकने के प्रति कोई गंभीर कदम नहीं उठाए। वो नहीं चाहते कि स्वास्थ्य विभाग का अमला संक्रमण रोकने में कामयाब हो जिससे टीएस सिंहदेव की छवि जनता की नजर में बेहतर बनें। क्योंकि भूपेश बघेल को यह डर हमेशा सताया रहता है कि सिंहदेव राज्य के अगले मुख्यमंत्री न बन जाए। प्रदेश में होती इस तरह की राजनीति पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहूल गांधी को संज्ञान लेते हुए भूपेश बघेल से आए दिन होती मौतों का जवाब लेते हुए फटकार लगाना चाहिए, ताकि पार्टी की छवि धूमिल होने से बचाई जा सके। खैर, मुख्यमंत्री जी आपसे गुजारिश है कि अभी वक्त राजनीति करने का नहीं, बल्कि जनता की मौत की बढ़ती संख्या और बढ़ते संक्रमण को रोकने का है। इसलिए इस दिशा में कुछ जरूरी कदम उठाइए जिससे रोजाना होती मौतों को रोका जा सके।

Scanned with CamScanner

बीजेपी हारी नहीं, ममता बैनर्जी जीती

अमित राय

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था- खेला होबे। सबको पता है कि ममता मैदान में डटने वाली और विरोधियों से दो-दो हाथ करने वाली नेता हैं। उन्होंने प. बंगाल में तीन दशक से जड़ जमाए वामपंथियों को सत्ता से उखाड़ फेंका था। सड़क की लड़ाई लड़ने में ममता की कोई सानी नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी के पक्ष में गोलबंदी पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा था। यही वजह है कि ममता के खेला पर किसी को इतना यकीन नहीं था कि 2016 के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटें टीएमसी के झोले में आ जाए। बीजेपी के पक्ष में मच रहे शोर के बीच कई राजनीतिक धुरंधर ममता की ताकत का अहसास करवा तो रहे थे, लेकिन वो भी दावे से नहीं कह पा रहे थे कि दीदी का जादू चलकर ही रहेगा। अब जब टीएमसी के खाते में 294 में से 211 सीटें आ चुकी हैं तो विश्लेषक कारण तलाश में और गहरे उतरने लगे हैं। इसी क्रम में यह भी कहा जा रहा है कि बंगाल की जनता ने दीदी को लगी चोट पर भी सहानुभूति दिखाई और उनकी झोली भर दी... अपना चुनावी क्षेत्र गईं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में 10 मार्च को चोट लगी जिसके बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा अचानक से बढ़ गया। एक तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अपने गुंडे भेजकर उनका पैर कुचलवाने का आरोप

Scanned with CamScanner

दीदी के लिए व्हील चेयर पर बैठना बंगाल चुनाव में साबित हुआ ट्रम्प कार्ड

10.2 वोट शेयर से भाजपा को 43 फीसदी वोट शेयर पर ले आए कैलाश विजयवर्गीय

राज्य कोई भी चुनाव में किसी पार्टी की जीत होती है तो किसी की हार। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से भाजपा ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के कंधों पर सवारी करके बंगाल में जो अपनी पैठ बनाई है वो कहीं न कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आश्वस्त करने वाली है। किस तरह से पार्टी के नेताओं ने बंगाल में ममता बैनर्जी द्वारा जनता के ऊपर किए गए अत्याचारों का प्रचार-प्रसार किया जिससे ममता के पार्टी के खुद के नेता उनसे खिन्न होकर भाजपा का दामन थाम बैठे। एक समय ऐसा था जब भाजपा बंगाल में नाम मात्र के सीटों के साथ बैठती थी। देखा जाए तो बंगाल का पूरा चुनाव ममता बनर्जी के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन ऐसी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा था कि टीएमसी को चुनौती दे। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ही ममता के सामने लड़ती हुई दिखाई दे रही थी। बंगाल चुनाव की घोषणा के बाद से ही यह आसार लगाए जा रहे थे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीति यहां सफल हो जाएगी। कुछ हद यह रणनीति सफल होती भी दिखाई दी। लेकिन ममता बैनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर जो ट्रम्प कार्ड खेला, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा। क्योंकि चुनाव रैली समापन के ठीक पहले ममता की यह चाल भाजपा नेताओं को भारी पड़ गई और एग्जिट पोल्स के अनुसार ममता बैनर्जी सरकार को यथावत चलाने की प्रबल दावेदार बनती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के वोट शेयर को देखे तो टीएमसी को 44 फीसदी और बीजेपी को 43 फीसदी मिला। 2016 के चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 44.9 फीसदी थी। वहीं, भाजपा उस समय 10.2 पर स्थिर थी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज लगभग तीन गुना अधिक वोट शेयर के साथ खड़ी है।

लगाया तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे ममता राजनीतिक ड्रामा बताया। पार्टी ने कहा कि ममता को पता चल गया है कि बंगाल की जनता उन्हें दुत्कार रही है तो वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश करने लगी हैं। हालांकि, ममता ने कहा कि नंदीग्राम में उन्हें चार-पांच लोगों ने धक्का दे दिया और वह गिर गईं, उनका पैर सूज गया। बहरहाल, अस्पताल से निकलने के बाद ममता बनर्जी वील चेयर से ही प्रचार करने लगीं। स्वाभाविक है कि इससे जुझारू नेता की उनकी छवि और भी मजबूत हुई। ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद पाठकों से पूछा था कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले से चुनाव में एख को नुकसान होगा? तब सिर्फ 21प्रति. लोगों को ही लगा कि यह चोट ममता बनर्जी को बीजेपी पर बढ़त दिला सकती है। 75प्रति. लोगों ने साफ-साफ कहा था कि इस घटना से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा जबकि 4प्रति. लोग यह फैसला नहीं कर सके थे कि ममता को चोट लगने से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा या फिर इससे कोई अंतर भी पड़ेगा या नहीं। लेकिन पाठकों की राय से अलग 2 मई को आए चुनाव परिणाम ने

Scanned with CamScanner

सबको चौंका दिया। किस इलाके में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है, कहां टीएमसी का कुनबा बिखर रहा है, इस तरह के विश्लेषणों से बताया जा रहा था कि किस-किस चरण में बीजेपी आगे निकल जाएगी और इतना आगे निकलेगी कि सत्ता तक पहुंच जाएगी। हालांकि, ऊपर के आंकड़े बताते हैं कि किस तरह बीजेपी हर चरण में टीएमसी से पीछे रही। याद रहे कि टीएमसी ने भले ही पश्चिम बंगाल में 211 सीटें जीत ली, लेकिन ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार का मुंह देखना पड़ा। उन्हें दो दशकों से भरोसेमंद रहे शुभेंदु अधिकारी ने शिकस्त दी जिन्होंने चुनाव से पहले टीएमसी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो क्या यह सवाल लाजिमी नहीं है कि जनता ने दीदी की चोट देखकर पूरे प्रदेश में उनके प्रत्याशियों को जीत दिलाई तो फिर खुद ममता को ही क्यों हरा दिया? पश्चिम बंगाल में हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव लम्बे समय तक इसलिये याद किए जाते रहेंगे, क्योंकि इस चुनाव में जिस नेता के दम पर और नाम पर भारी बहुमत से चुनाव जीते गए वह नेता स्वयं अपनी एक सीट हार गई। इस हार के बावजूद ममता को तीसरी बार प्रदेश की बागडोर संभालने का संवैधानिक अधिकार तो संविधान का अनुच्छेद 164 (4) देता ही है। साथ ही अकेले दम पर अपने 293 में से 213 प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराना उनको सत्ता में वापसी का नैतिक अधिकार भी देता है। वैसे भी न तो कोई मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव हारा है और ना ही हारा हुआ नेता पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है। यही नहीं बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री बनने की परम्परा भी नई नहीं है। लेकिन पार्टी को चुनाव जिताने वाली शख्सियत का स्वयं हार जाना पहली घटना है।

हारे हुए नेता पहले भी बने मुख्यमंत्री

लोकतांत्रिक गणराज्य भारत के संसदीय चुनाव के इतिहास में किसी भी व्यक्ति का बिना विधानमण्डल का सदस्य बने मुख्यमंत्री नियुक्त होना कोई नई बात नहीं है। सन् 1952 में पहले आम चुनाव के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के आधार पर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मद्रास राज्य का तथा मोरारजी भाई देसाई को बम्बई प्रान्त (वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात) का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था।

बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में कामयाब रहीं ममता बनर्जी, नतीजों में दिखा सीधा असर

हालिया पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी प्रदेश के मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने में सफल रहीं, जिसका सीधा असर नतीजों पर पड़ा है और टीएमसी तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने वाली तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोटों को मजबूत करने में सफल रही और इसका चुनाव के नतीजों पर सीधा असर पड़ा। 63 मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में से 61 निर्वाचन क्षेत्रों में हुए थे और तृणमूल कांग्रेस ने उनमें से 58 में, बीजेपी ने दो में और एक में संयुक्त मोर्चा ने जीत हासिल की। मुस्लिम बहुल सीटों के अधिकांश हिस्से चार जिलों- मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24-परगना और दक्षिण 24-परगना में हैं। मुर्शिदाबाद में कुल 22 विधानसभा सीटों में 16 मुस्लिम

Scanned with CamScanner

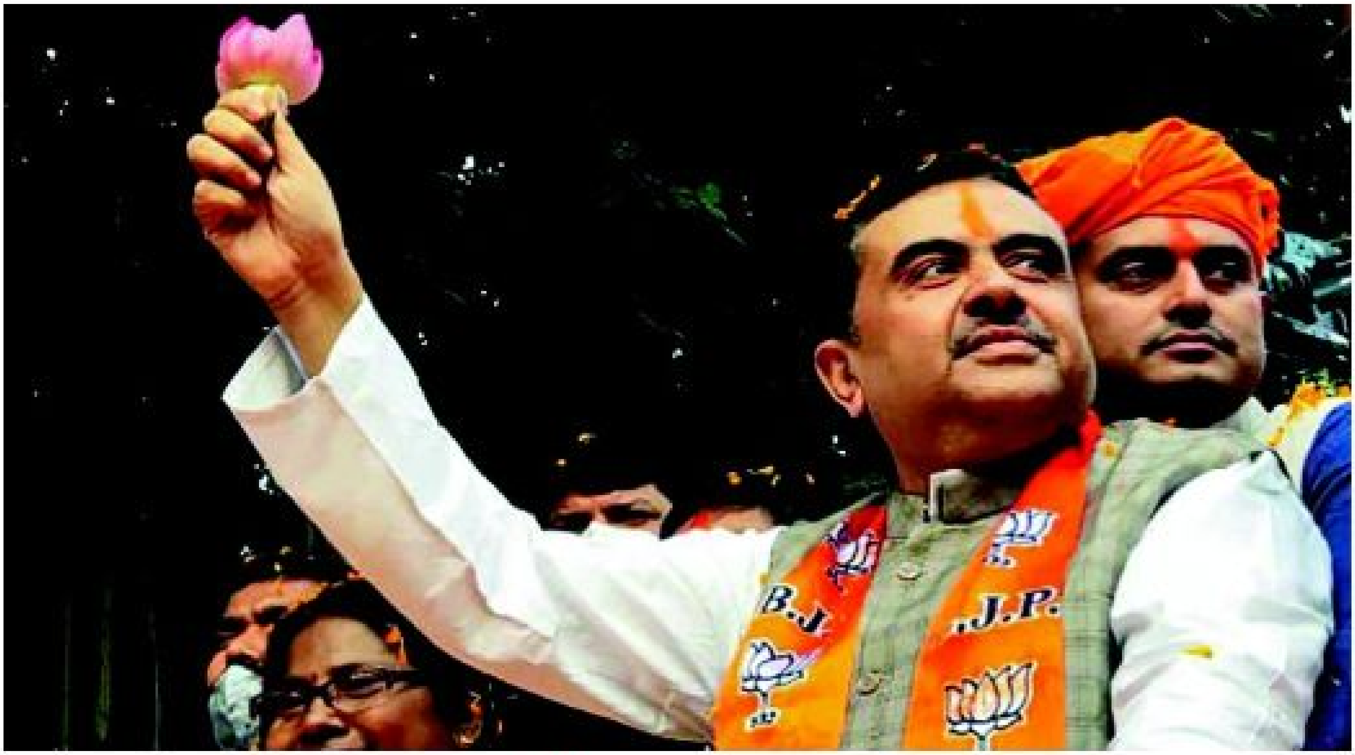

बहुल सीटें हैं, बाकी तीन जिलों में 9 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि, इन कुल 63 सीटों में से 61 में चुनाव हुए थे, क्योंकि दो जिलों - समसरगंज और जंगीपुर में उम्मीदवारों की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। बाकी 61 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 58 सीटें हासिल करने में सफल रही। दिलचस्प बात यह है कि इन 58 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 40 हजार या उससे अधिक मतों के अंतर से 30 सीटें जीतने में सफल रही। मालदा जिले के सुजापुर में एसके जियाउद्दीन, फरक्का में मोनिरुल इस्लाम, भगांगोला में इदरीस अली- मुर्शिदाबाद में दोनों उम्मीदवार कुल मतों के 50 प्रतिशत से ऊपर वोट पाकर 50 हजार से अधिक वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी को उत्तरी दिनाजपुर में केवल एक सीट और मुर्शिदाबाद जिले में दूसरी सीट मिली, जबकि भारतीय सेक्युलर मोर्चा (संजुक्त मोर्चा का सहयोगी) दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में एक सीट पर कामयाब रहा।

बीजेपी के हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से सतर्क हुई ममता

बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की संभावना देखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आशंका जताई थी कि अगर मुस्लिम वोट तृणमूल के खाते में नहीं आते हैं तो यह उनकी हार का कारण बन सकता है। यह उनके भाषणों में स्पष्ट था, जहां उन्होंने चुनावी सभा में कहा था कि जो व्यक्ति हैदराबाद से बंगाल का दौरा कर रहा है, उसे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से पैसा मिला है। उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा था। ममता फुरफुरा शरीफ के मौलवी अब्बास सिद्दीकी पर भी बरसी थीं, जिन्होंने इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) का गठन किया और चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस और वाम मोर्चे से हाथ मिलाया। मुस्लिम वोट बैंक बंगाल चुनाव में एक बड़ा और निर्णायक कारक है। लगभग साढ़े तीन दशकों तक, मुसलमानों को वाम मोर्चा का वोट बैंक माना गया, जिसने राज्य में 34 वर्षों तक शासन किया।

मुसलमानों ने टीएमसी पर जताया भरोसा

बदलाव तब आया, जब सिंगुर और नंदीग्राम आंदोलन के दौरान टीएमसी ने किसानों, मजदूरों और मुसलमानों और खासकर गरीबों को एकजुट किया और मुसलमानों ने वामपंथियों से मुंह मोड़कर तृणमूल कांग्रेस में अपनी निष्ठा जताई। साल 2011 में वाम मोर्चा मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने में सफल रहा और 45 प्रतिशत अल्पसंख्यक वोटों का प्रबंधन किया, लेकिन तत्कालीन सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश ने ममता बनर्जी को सत्ता दिला दी। विश्लेषकों ने कहा, परिणाम साबित करते हैं कि ममता मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने में सफल रहीं। तृणमूल कांग्रेस को आईएसएफ का डर था, मुस्लिम धर्मगुरु के नेतृत्व में नवोदित राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस का खेला बिगाड़ सकता था लेकिन वे मुस्लिम वोटों को बांटने में कामयाब नहीं हो पाए।

Scanned with CamScanner

निजी अस्पतालों में सांसों की कालाबाजारी!

कौशल

यह मजबूरी ही है कि चिकित्सा क्षेत्र में सरकारी व्यवस्थाओं को असंतोषजनक मानते हुए व्यक्ति निजी अस्पतालों की ओर रुख करता है और जब वहां ठगा जाता है तब उसे महसूस होता है कि काश, सरकारी में ही भर्ती हो जाते।...खैर यह तो सामान्य बात हो चुकी है। अबतक तो निजी अस्पताल मोटे बिलों के कारण ही चर्चा में रहते आए हैं, लेकिन मौजूदा कोरोना दौर में निजी अस्पतालों में दलाल पनप गए हैं जो जरूरी जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। इनमें चिकित्सा के पवित्र पेशे से जुड़े लोग भी संलिप्त हैं।

सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति निजी अस्पताल में इसलिए भर्ती होता है क्योंकि उसे वहां अच्छी सार-संभाल का भरोसा होता है। व्यक्ति पैसे की चिंता नहीं करता, सिर्फ सार-संभाल और उपचार की सुविधाओं पर भरोसा करता है। निजी अस्पतालों की पहली शर्त ही होती है कि वहां भर्ती होने पर सारी दवाएं उसी अस्पताल की फार्मेसी से लिया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे में जिस भी दवा की जरूरत है, निजी अस्पताल की फार्मेसी ही उपलब्ध कराती है। जो लोग भर्ती होते हैं उनके परिजनों को भी यह निश्चिंतता होती है कि निजी अस्पताल में ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन, पिछले दिनों कोविड के मामलों में जरूरी इंजेक्शन की पर्ची मरीजों के तीमारदारों को थमाई जाने लगी है। रेमडेसिविर से लेकर टोसिल (एमआरपी करीब 40 हजार रुपये) और उसके विकल्प के रूप में रेमेडिशिविर इंजेक्शन चिकित्सक पर्ची पर लिखकर परिजनों के हाथ में थमा रहे हैं। परिजनों की परेशानी यहीं से शुरू हो रही है कि एक तरफ कोई भी दवा अस्पताल की

Scanned with CamScanner

फार्मेसी से लेने का नियम है, दूसरी तरफ महंगे इंजेक्शन की पर्ची उन्हें क्यों थमाई जा रही है। जब वे पैसा देने को तैयार हैं तो व्यवस्था अस्पताल को ही करनी चाहिए। जबकि निजी अस्पताल वाले, हमारे यहां यह दवाई उपलब्ध नहीं है, कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।

बस यहीं से जिन्दगी बचाने का कालाबाजार शुरू हो रहा है। सीधा-सा प्रश्न है जो सामान्य व्यक्ति भी करेगा कि जब इतना बड़ा निजी अस्पताल इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो मरीज का परिजन कहां से कर पाएगा। अधिकतर तो फार्मेसी शब्द भी नहीं जानते, सिर्फ दवाई की दुकान से ही पुकारते हैं। ऐसे में अब उन्हें किसी जानकारी की दरकार होती है जो महंगी दवाई उचित दर पर दिला दे। हालांकि कुछ ही देर में उन्हें जानकारी अस्पताल में ही उपलब्ध हो जाते हैं। पहले तो वे तथाकथित जानकारी एक दो मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर का पता देते हैं, लेकिन वहां से इंजेक्शन उपलब्ध हो रहा होता तो

बस यहीं से जिन्दगी बचाने का कालाबाजार शुरू हो रहा है। सीधा-सा प्रश्न है जो सामान्य व्यक्ति भी करेगा कि जब इतना बड़ा निजी अस्पताल इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो मरीज का परिजन कहां से कर पाएगा। अधिकतर तो फार्मेसी शब्द भी नहीं जानते, सिर्फ दवाई की दुकान से ही पुकारते हैं।

क्या अस्पताल की फार्मेसी नहीं मंगवा लेती। अब वह जानकारी अपना खेल शुरू करता है और किसी और जानकारी के नंबर देता है। दूसरी तरफ निजी अस्पताल परिजनों के सामने खुद को लाचार-बेबस साबित करने में भी कसर नहीं छोड़ता। मरता क्या न करता, अब वह दूसरा जानकारी जो भी रस्ता दिखाता है उसी पर चलना तीमारदार की मजबूरी हो जाती है।

अब 40 हजार वाले टोसिल इंजेक्शन के लिए मुंहमांगा दाम देना तीमारदार की मजबूरी हो जाती है। एक तीमारदार ने पीड़ा सिर्फ इस शर्त पर बताई कि उसका नाम कहीं नहीं बताया जाएगा क्योंकि फिर उसके बीमार परिजन के उपचार में कोताही की पूरी आशंका उसे परेशान किए रहती है। उस तीमारदार ने टोसिल इंजेक्शन एक लाख 60 हजार में खरीदा। इस बात पर विश्वास करने

Scanned with CamScanner

के लिए एक ही आधिकारिक उदाहरण काफी है कि उदयपुर में 21 अप्रैल 2021 को स्पेशल पुलिस ने डेकॉय ऑपरेशन किया जिसमें दलालों ने रेमडेसिविर के 35 हजार रुपये वसूले। पकड़े गए दो युवकों में से एक चिकित्सक (कॉर्डियोलॉजिस्ट) था और एक एमबीबीएस का सेकंड ईयर का स्टूडेंट, दोनों एक निजी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के हैं। हालांकि, अब तक यह सामने नहीं आया है कि वे रेमडेसिविर कहां से प्राप्त कर रहे थे। पुलिस यदि इस पूरे खेल की गहराई से जांच करेगी तो कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें बड़े नाम भी सामने आएंगे। अब जब रेमडेसिविर का कालाबाजार 35 हजार का है जिसकी एमआरपी अब 2 से 4 हजार के बीच है, ऐसे में 40 हजार एमआरपी वाला इंजेक्शन काले बाजार में सवा-डेढ़ लाख की कीमत तो रख ही सकता है।

सवाल यह है कि इंजेक्शन की जरूरत जानकारी को तुरंत कैसे पता चल जाती है। इसमें निजी अस्पतालों के कतिपय कार्मिकों की भूमिका को भी टटोला जाना चाहिए। यह भी जांच का विषय है कि परिजन द्वारा लाए गए ऐसे महंगे इंजेक्शन का इंद्राज मरीज की मेडिकल रिपोर्ट में होता है या नहीं, क्या पता अंदर इंजेक्शन लगाया भी या नहीं, परिजन तो सामने होते नहीं। फिर उस इंजेक्शन की बिलिंग कहां से होती है। होती भी है या नहीं। भले ही एमआरपी का ही बिल हो, लेकिन यह तो पता चलेगा कि अमुक इंजेक्शन उपलब्ध कहां पर है। लेकिन, ऐसा शायद ही किया जाता होगा। जबकि, लाइफ सेविंग वाले इन महंगे इंजेक्शन में निर्माण से लेकर मरीज को लगाने तक की पूरी ट्रेल का लेखा-जोखा अनिवार्यत: रखने का प्रावधान है।

लगे हाथों यह भी चर्चा कर लेते हैं कि जो इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध नहीं हैं वह उपलब्ध कहां से होता है। दरअसल, निजी अस्पताल सिर्फ शहर में ही नहीं होते, गांवों में भी तो हैं। वे भी ऐसे महंगे वाले इंजेक्शन का करीब-करीब पांच से दस का स्टॉक तो रखते ही हैं। चूंकि, कोरोना में अधिकतर मरीज शहरी क्षेत्रों में ही कोविड की अनुमति वाले निजी अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं, ऐसे में इंजेक्शन की शॉर्टेज शहरी क्षेत्र में हो सकती है, हालांकि उन्हें इसका इंतजाम पु ता करना चाहिए जो कि उनकी जि मेदारी है। खैर, ग्रामीण क्षेत्रों या उन निजी अस्पतालों में जहां इस तरह के गंभीर मामले भर्ती नहीं होते, वहां पड़े इंजेक्शन इसी तरह के काला बाजार का हिस्सा बन जाते हैं और अभी बन रहे हैं। एक निजी अस्पताल में दूसरे निजी अस्पताल के जानकार घूम रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है कि उनके यहां मरीज भर्ती नहीं हो

Scanned with CamScanner

रहे, इंजेक्शन से ही खर्चा निकल रहा है।

ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पकड़ने का सिस्टम नहीं है। सारे निजी अस्पतालों से अचानक छापा मारकर ऐसे इंजेक्शन का बिलिंग सहित रिकॉर्ड, मैन्युफैक्चरर से सीएन्डएफ, डिस्ट्रीब्यूटर तक के कागजों की ट्रेल और जिस मरीज को लगाया गया है उसकी मेडिकल रिपोर्ट और उसकी बिलिंग जब्त करके सरकार जांच कर सकती है। चोर की दाढ़ी में कहीं न कहीं तो तिनका मिल ही जाएगा। बस ढूंढकर निकालने में ईमानदारी बरती जाए तो। साथ ही, निजी अस्पतालों की उन्हीं की फार्मेसी से दवा खरीदने की अनिवार्यता को यदि मान्यता दी जा रही है तो ऐसे इंजेक्शन की उपलब्धता भी उन्हीं की जिम्मेदारी में लाया जाए और इस जिम्मेदारी को उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत लाया जाए, वर्ना यहां तो चित भी अपनी और पट भी अपनी वाला खेल सामने नजर हो ही रहा है।

इन सारे मामलों में मरीज के परिजनों पर मरता क्या न करता वाली कहावत लागू होती है, ऐसे में सरकार को डेकॉय ऑपरेशन बढ़ाने चाहिए। अब से पहले रूण हत्या रोकने के लिए सरकार ने लगातार डेकॉय ऑपरेशन किए थे, अब इन जरूरी इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए डेकॉय ऑपरेशन की जरूरत आन पड़ी है। सिर्फ पकड़ने तक ही नहीं, इसकी तह तक जांच की जानी चाहिए ताकि उन डिस्ट्रीब्यूटर्स और उन निजी अस्पतालों का भी काला चिट्ठा उजागर हो सके।

सबसे खास बात यह कि हमलोग जो सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों को दोयम दर्जे का मानने लगे हैं, उनका मूल्य इसी तरह के अनुभवों के साथ समझ में आता है। आपको बता दें कि 40 हजार की कीमत वाला इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में सरकार मरीज को (उसी को जिसे वास्तव में इसकी जरूरत आन पड़ती है) निःशुल्क मुहैया कराती है और कराए भी हैं। ऐसे में सरकारी व्यवस्थाओं में यदि हम सहयोगी बनें, तो निजी अस्पतालों की बढ़ती मनमानी पर स्वतः लगाम लगनी शुरू हो जाएगी। उदाहरणतः उद्योगपतियों, समाजसेवियों, भामाशाहों ने सरकारों के आह्वान पर ऑक्सीजन की आपूर्ति की ओर कदम बढ़ाए तो 24 घंटे में तस्वीर बदल गई। इसी तरह उद्योगों से जुड़ी संस्थाएं उनसे जुड़े निजी अस्पतालों में नैतिक मूल्यों की स्थापनाा के लिए प्रयास करें तो सुधार का दस प्रतिशत ही जीवन और मौत के काले बाजार को खत्म कर देगा।

Scanned with CamScanner

दिल्ली में कोरोना से हाहाकार

कोरोना के एक साल हो जाने के बाद देशव्यापी कठिन लॉकडाउन से हम कोरोना वैक्सीन तक आ गए लेकिन हमने क्या सीखा? क्योंकि आज एकबार फिर देश में माहौल बन रहा है कि जैसे स्थितियां सरकारों के हाथ से बहार निकल गई हैं। लगातार बढ़ते मामले के साथ ही लोगों में खुद-ब-खुद लॉकडाउन का डर पनप रहा है। देशभर में एक बार फिर कोरोना बड़ी आमकता से अपने पैर पसार रहा है। एक बार फिर ये बड़ी तेज़ी से लोगों की जिंदगियां लील रहा है। कोरोना वायरस का तांडव भारत ने पिछले साल की शुरुआत में देखा था।

मणिशंकर पांडे

कोरोना के एक साल हो जाने के बाद देशव्यापी कठिन लॉकडाउन से हम कोरोना वैक्सीन तक आ गए लेकिन हमने क्या सीखा? क्योंकि आज एकबार फिर देश में माहौल बन रहा है कि जैसे स्थितियां सरकारों के हाथ से बहार निकल गई हैं। लगातार बढ़ते मामले के साथ ही लोगों में खुद-ब-खुद लॉकडाउन का डर पनप रहा है। देशभर में एक बार फिर कोरोना बड़ी आमकता से अपने पैर पसार रहा है। एक बार फिर ये बड़ी तेज़ी से लोगों की जिंदगियां लील रहा है। कोरोना वायरस का तांडव भारत ने पिछले साल की शुरुआत में देखा था। बड़ा सवाल यही है कि हमने माहमारी के एक साल बाद भी क्या कुछ सीखा या हम अपने पुराने ढर्रे पर ही रहे। आज जो देश में हालत है उसके लिए कौन ज़िमेदार है?

खासकर देश की राजधानी दिल्ली जो केंद्र सरकार के सबसे पास है लेकिन आज जिस तरह से केस बढ़ रहे और लोग भयभीत हैं वो सरकारों की तैयारियों की पोल खोलते हैं। दिल्ली में आज अबतक के सबसे अधिक केस आ रहे हैं। लोगों को अस्पताल में ठीक इलाज नहीं मिल रहा है। मज़दूर वर्ग एकबार फिर भयभीत है कि कहीं सरकार अचानक से फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा न

Scanned with CamScanner

कर दे। इन सब स्थितियों के बीच सरकार टीवी चैनलों के माध्यम से बड़े बड़े दावे भले कर ले लेकिन जमीन पर सरकारी दावे फेल होते दिख रहे हैं। राजधानी में एकबार फिर मरीजों को कोरोना के नाम पर इलाज के लिए मना किया जा रहा है। दिल्ली की संक्रमण दर देश की औसत से कहीं अधिक है। दिल्ली में कोरोना संमण दर 12.44 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 9 फीसदी है। दिल्ली सरकार ने संक्रमण के बढ़ने के बाद से जाँच की अपनी गति भी बढ़ाई जो पिछले दिनों कम कर दी गई थी। अब दिल्ली सरकार पैनिक मोड में दिख रही है। लगातार बेड न मिलने की खबरों के बीच दिल्ली सरकार ने 14 निजी अस्पताल पूर्ण कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने शहर में 14 निजी अस्पतालों को पूर्ण कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया और उन्हें अगले आदेश तक गैर कोविड-19 मरीजों की भर्ती नहीं करने का निर्देश दिया।

मज़दूर वर्ग में भय का माहौल

देश के साथ ही दिल्ली में भी माहमारी फैल रही है लेकिन अगर हम सभी सरकारों के काम करने का तरीका देखे तो ऐसा लगता है महामारी के साथ ही सरकारों के नीतियों की भी पुनरावृत्ति हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रोजाना टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना के आकड़े बता रहे हैं और रोजाना कोई नयी घोषणा कर रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों के साथ ही लोगों में खुद ब खुद एक डर का माहौल बन रहा है, खासकर मज़दूर वर्ग डरा हुआ है कि एकबार फिर माहमारी के नाम पर लॉकडाउन न कर दिया जाए। हालांकि अभी सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिक रहते हैं। इनमें एक बड़ी संख्या दिहाड़ी मज़दूरों की है जो रोज कमाते-खाते हैं। यहां पिछले लॉकडाउन में मज़दूरों की हालत बदतर हो गई थी। उसी को याद करते हुए ये मज़दूर बुरी तरह डरे हुए हैं। इनमें से एक बड़ा तबका पलायन कर रहा है। क्योंकि उसे सरकारों पर भरोसा ही नहीं है। महामारी के बाद भी सरकार इन्हे ये आश्वस्त नहीं कर पाई है कि वो उनकी सुरक्षा कर सकती है।

Scanned with CamScanner

India's Covid mismanagement : Thousands die for want of ventilators, medicines

Stumbling from one misstep to the next, the Modi government is lost in a labyrinth of its own making. Only now it's dawning on the electorate that their priorities were wrong

In Lucknow, Chief Minister Yogi Adityanath could, if he wants, smell the stench of death. For the last several days, the city's crematoriums have been inundated with Covid corpses. So much so, with people taking a morbid interest in the goings on at the city's largest cremation ground, the authorities had to put up an "opaque" fence all around it! Out of sight, out of mind?

Hardly. Governments, both central and those of the states, seem to have lost the plot to the coronavirus, fumbling along in bumbling disarray. And it doesn't matter which party is in power where. If Gujarat's Chief Minister Vijay Rupani and Maharashtra's Uddhav Thackeray have no clue, Prime Minister Narendra Modi looks no less lost. Surprisingly unaware of responsibility. Stumbling from one misstep to the next. Lost in a labyrinth of their own making.

In its second coming, Covid-19 is treating India like it treated Italy and Brazil (and Spain) with the first wave. And it's not just in Lucknow, cremation grounds

Scanned with CamScanner

across India are witness to unseemly hurry thwarted by pile-ups of Covid dead. The dead are being burned well past dusk, right up to and beyond the midnight hour. Similarly, burial grounds can't locate space to bury the Covid-dead. Besides, consigning the dead now costs a packet, at crematorium as well as at the graveyard.

Chances are if you are rich, if you're "connected", with "jugaad" written into your pedigree, you would be able to survive Covid-19, nary a worry. For instance, Bollywood actors, who post their Covid-19 statuses on Twitter and Instagram, move into the best of hospitals without a hitch. Not the common man, even the middle-class Twitterati. Only the lucky few among these lesser mortals are able to find a hospital bed and oxygen to beat the coronavirus.

The other day a "national award-winning cyclist" died after two private hospitals in Pune refused to admit him, and the third, a government installation, admitted him only to allegedly "neglect" him. This guy got his features plastered all over the media because his was a known face, but the common guy, the Aam Aadmi, will pass away, vanish into a black-hole the other side of the Invisible Line, no

questions asked!

And, now with the Government putting the brakes on the over-the-counter availability of Remdesivir, there's a roaring black market in the drug all across the country. In Karnal, Haryana, a vial of Remdesivir with MRP Rs. 250 is selling at Rs 15,000-Rs18,000 in the black market. That said, the shortage of ventilators is the biggest killer in the realm. Nobody's sure whether Remdesivir is effective or not, but hundreds are suffocating for want of ventilators in hospitals.

In Ahmedabad, where cremation grounds are crowded with the Covid-dead, the standstill caravan of ambulances outside hospitals tell another story - of acute shortage of hospital beds, prompting people to cynically retort, "But, then, when did we vote for hospitals, we voted for Ram Mandir, didn't we?" Like they say, the sting is in the tail: Only now it's dawning on the electorate that their priorities were wrong.

That said, it took countless dead to bring home the basic truth. Social media is awash with posts and comments, tweets and Instagram stories, of people who have woken up to the realization that temple domes and masjid minarets do not count if there isn't Remdesivir, the ventilator and the oxygen. That in today's

Scanned with CamScanner

Covid world, death is cheap.

Entire families are getting infected and nobody knows for sure whether it's the old who are succumbing more, or are the young too collapsing lifeless in big numbers. All you get to hear and see (on TV and newspapers) are cold lifeless statistics. And, then, you're told of Covid-appropriate behaviour while Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah and politicians of all hues address Covid-inappropriate public rallies without a care in the world.

The question: Do politicians only care for elections, to win them at any cost? Unlike SARS, Covid-19 is not going away anytime soon. The severity of the second wave is proof that the novel coronavirus has quietly adapted to earth conditions and is mutating to spread across geographies. A mahamandaleshwar of a Jabalpur temple who took a dip at the Kumbh in Haridwar died of Covid-19 the other day and it's reported that he had taken both doses of the Covid-19 vaccine before he took the 'shahi snaan!'

The point is, everything about the novel coronavirus, including the vaccines, is sort of fluid at this point in time. If the Government of the day does not understand this, then we as a nation might as well do a Padmavati. Just for reminders, India reported its highest number of Covid cases for the eighth time in nine days on April 17. This, when China reported record economic growth as it rebounded from the pandemic slump. Should Narendra Modi take some Covid lessons from Xi Jinping?

Maybe yes. India's total Covid cases had raced to 14,074,564 and Covid deaths to 174,308. Nobody lives forever, but to die from Covid is such a waste. A novel coronavirus comes out of nowhere and takes away life in hundreds of thousands. For millions of Indians who sat through the first Covid wave, the second Covid wave is unnerving. And, for all we know, there's a massive vaccine crisis in the making even as helpless and hopeless people despair.

(National Hearald)

Scanned with CamScanner

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

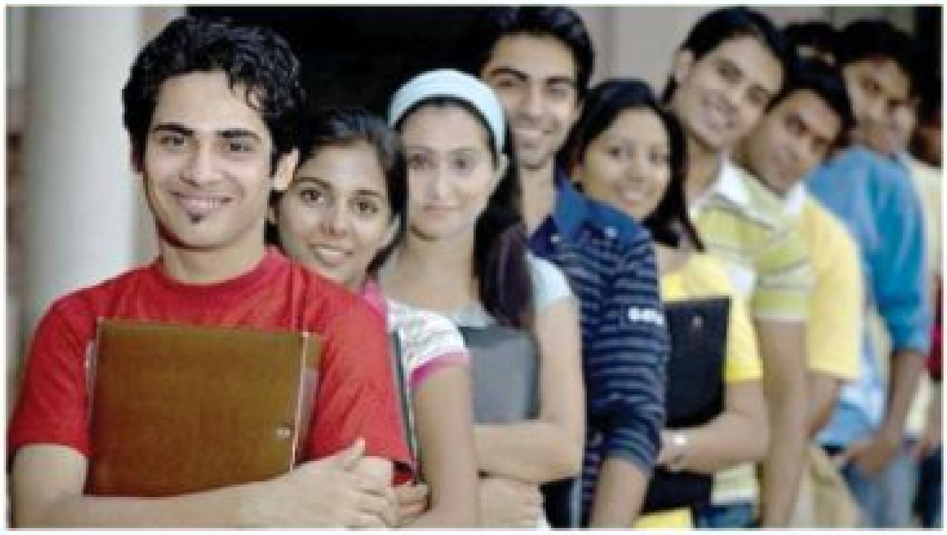

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) 9826064596

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

Scanned with CamScanner